◆ सितम्बर, 2022 ◆ मूल्य: 35/-

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से अनुप्राणित

अभ्युदय वात्सल्यम्

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका

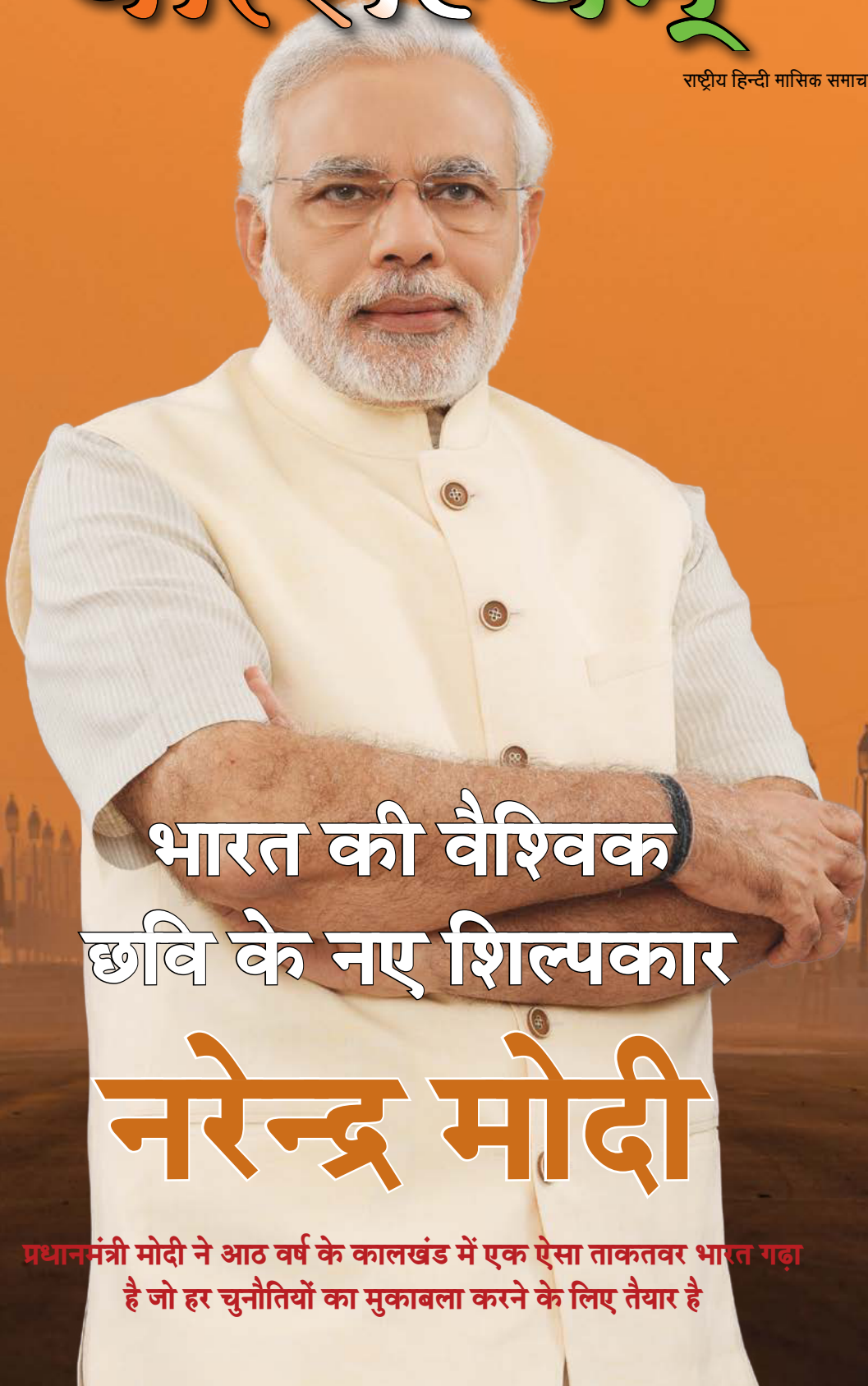

भारत की वैश्विक छवि के नए शिल्पकार

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आठ वर्ष के कालखंड में एक ऐसा ताकतवर भारत गढ़ा है जो हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है

www.saiworldcity.co.in

SAI
WORLD CITY
PANVEL

A WORLD WITH EVERYTHING WITHIN

JUST 5 MINS. FROM NAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

MAHARERA REGISTRATION NO.: PHASE 1 - P52000006318 I PHASE 2 - P52000022708 (https://maharera.mahaonline.gov.in)

Artist's Impression

PROJECT HALLMARKS

- 32 Acre Mega Township
- G+33 Storeyed Tower
- 2, 2.5, 3 & 4 BHK Luxury Homes
- Themed Landscaping
- International Lifestyle

MAHARERA REGISTRATION NO. PHASE I - P51700002446
PHASE III - P52000029168 | https://maharera.mahaonline.gov.in

Artist's Impression

AN EMPIRE FOR MODERN DAY KINGS AND QUEENS

PROJECT HALLMARKS

- 18 Acre Kingdom
- G+40 Storeyed Tower
- 2, 3 & 4 BHK Luxury Homes
- Commercial Mall with G+2 storeys
- Designer Podium Garden
- Athena Clubhouse

2783 1000 | Email: enquiry@paradisegroup.co.in I www.paradisegroup.co.in

Site & Sales Office: Sai World Empire, Opp. Kharghar Valley Shilp (CIDCO Colony), Kharghar

Site & Sales Office: Sai World City, Palaspe Phata Junction, Panvel - 410 206.

Follow us on:

PARADISE® GROUP
Your World. Our Vision.
ISO - 9001: 2015 Certified Organization

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से अनुप्राणित

अभ्युदय वात्सल्यम्

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका

■ वर्ष-15 ■ अंक-02 सितम्बर, 2022 ■ मूल्य- 35/-

संस्थापक सम्पादक : कृपाशंकर तिवारी
प्रधान सम्पादक : आलोक रंजन तिवारी
प्रबन्ध सम्पादक : शिवा तिवारी
दिल्ली - एनसीआर ब्यूरो : आशुतोष मिश्रा
लखनऊ ब्यूरो : हरिभजन शर्मा
विज्ञापन प्रबंधक - संजय सिंह
ग्राफिक डिजाइनर - अनमोल शुक्ल, अनिल मशालकर
फोटोग्राफर - हार्दिक रामगुड़े, राहुल पारकर

पत्राचार कार्यालय: आर - 2/608, आरएनए प्लाजा, निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प.), मुंबई - 400104

एनसीआर ब्यूरो : 748, वास्टो महागुन मॉडर्न, सेक्टर - 78, नोएडा - 201 305. सम्पर्क : 9167615266

लखनऊ ब्यूरो : 101, श्रद्धा विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ - 226 028 . सम्पर्क : 9452222370 / 8318252532

कृपा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कृपाशंकर तिवारी द्वारा विनय ग्राफिक्स, युनिट नम्बर 13, रवि इंडस्ट्रियल प्रेमायसेस, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - 400093 से मुद्रित एवं आर - 2/608, आरएनए प्लाजा, निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प.), मुंबई - 400104 से प्रकाशित।

सम्पादक : आलोक रंजन तिवारी
पंजीकृत कार्यालय: आर - 2/608, आरएनए प्लाजा, निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प.), मुंबई - 400104

दूरभाष: 022 -26771428 / 9967718221 / 7800611428
ई-मेल: kst@avmagazine.co.in
वेबसाइट : www.avmagazine.co.in

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं से सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका में प्रदर्शित समस्त पद अवैतनिक हैं। पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र मुंबई होगा।

विशेष आलेख
भारत की भूमिका विश्व गुरु के दायित्व बोध से अनुप्राणित होनी चाहिए
पृष्ठ 06

आलेख
डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने वाले प्रधानमंत्री
पृष्ठ 14

आन्तरिक

रेलवे
बुलेट स्पीड में दौड़ता रेलवे का ग्रोथ इंजन
पृष्ठ 40

साक्षात्कार
जितना 75 सालों में किया उससे ज्यादा अगले 10 सालों में करेंगे
पृष्ठ 46

22 नरेन्द्र मोदी : कालजयी राजनीतिक जीवन यात्रा

विशेष आलेख

26 भारत बदलाव की छोर पर खड़ा है

32 टॉप गियर में रोड सेक्टर

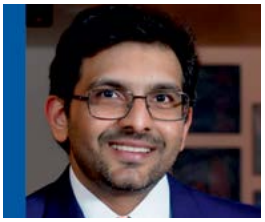

38 मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य को लेकर चलना होगा

50 भारत बनेगा विश्व लीडर

आत्मनिर्भरता से ही पूरा होगा विकसित राष्ट्र का संकल्प

आलोक रंजन तिवारी

आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। निश्चित ही अब तक की यात्रा गौरवशाली और समृद्धि भरी रही है। जीवन के विविध क्षेत्रों में राष्ट्र ने आशातीत प्रगति की है। बात चाहे आयु प्रत्याशा की हो, आर्थिक गतिशीलता की या फिर विज्ञान-प्रौद्योगिकी के विकास और सामाजिक सह-अस्तित्व की, राष्ट्रीय प्रगति संतोषजनक रही है। लेकिन, क्या इस हासिल उपलब्धि से संतोष कर लेने मात्र से ही हमारा काम चल जाएगा या नई राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए नई राह चुननी-बुननी पड़ेगी? आखिर आज से 25 वर्ष बाद जब राष्ट्र अपनी आजादी की 100वीं वर्षगाँठ मना रहा होगा तब उसका स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी विचार करना ही होगा।

भारत एक जनांकिकीय लाभांश वाला देश है। यानी इसके पास सबसे बड़ा युवा श्रम बल है जो देश को तेजी से आगे ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन, इस क्षमता का उपयोग तभी हो पाएगा जब ये युवा बेहतर कौशल से लैस हों तथा गतिशील आर्थिक गतिविधियों के प्रति सहज हों। इसके लिए दो महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं, पहला गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक शिक्षा और दूसरा निजी क्षेत्र के उद्यमों का विकास और प्रोत्साहन। अब, अगर पहले बिंदु को देखें तो नई शिक्षा नीति एक उम्मीद जगाती है तथा यह इस रूढ़ि को तोड़ने का आग्रह करती है, जहाँ व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कमतर माना जाता है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 19 से 24 वर्ष के आयुवर्ग वाले भारतीय कार्यबल में से मात्र 5 प्रतिशत लोगों ने ही व्यावसायिक शिक्षा हासिल की है जबकि अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में यह दर क्रमशः 52, 75 तथा 96 प्रतिशत है। अतः, आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सहजता स्थापित की जाए, तभी 100वीं वर्षगाँठ पर देश अधिक उन्नत हो सकता है। निजी उद्यमों के प्रति सहजता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद दुनिया काफी तेजी से बदली है और बिना निजी क्षेत्र की भागीदारी के आर्थिक विकास संभव नहीं है।

इसके अलावा जिस एक क्षेत्र पर अधिक ऊर्जा से काम करने की आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य। कोविड महामारी ने इस छिपी जरूरत को प्रत्यक्ष कर दिया है। आज से 25 साल बाद के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत क्रमशः एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाला देश बन सकेगा और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो सकेगा। इस संदर्भ में कुछ वैश्विक उदाहरणों की चर्चा करें तो दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्वाधिक खर्च करने वालों में देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी है जो अपने जीडीपी का लगभग 20 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। अमेरिका अपने नागरिकों को प्राइवेट, फेडरल एवं पब्लिक फण्ड सहित कुल तीन प्रकार के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वहाँ जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत स्वास्थ्य संरचनाओं पर खर्च किया जाता है। नैशनल हेल्थ सिस्टम के माध्यम से वहाँ की राष्ट्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यूरोपीय यूनियन के देशों में किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक नागरिक को बीमा सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई है। इस संदर्भ में फ्रांस का उदाहरण अनुकरणीय है, जहाँ सरकारी व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वोत्तम श्रृंखला मौजूद है। एशियाई देशों में जापान व सिंगापुर का स्वास्थ्य अवसंरचना भी वैश्विक गुणवत्ता वाली है। 100वीं वर्षगाँठ पर भारत भी स्वास्थ्य गुणवत्ता के वैश्विक मानकों में शामिल हो, इस अनुरूप कार्य करना होगा। उपरोक्त उदाहरण इसमें मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं।

इस बात को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक विकास की गति को बढ़ाए बिना एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों- कृषि, उद्योग और सेवा-पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चूँकि देश की सर्वाधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, इसलिए इसे लाभ की स्थिति में लाना ही होगा। आज भारतीय कृषि के घाटे के सौदे को कुछ तथ्यों के माध्यम से बताना चाहें तो भारत में जहाँ एक कृषक श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता मात्र 200 डॉलर के आसपास है, वहीं नार्वे में यह लगभग पाँच गुना और यूएसए में यह बारह गुना से भी अधिक है। इस स्थिति को दूर करने के लिए दीर्घकालिक और स्थायी उपायों पर काम करना होगा। इसके अतिरिक्त एमएसएमई उद्योगों के विस्तार के माध्यम से आर्थिक भागीदारी को नीचे तक पहुँचाने, स्टार्ट-अप के लिए उत्साहजनक इकोसिस्टम तैयार करने, भारी उद्योगों को स्थापित करने तथा विदेशी निवेश के माध्यम से पूंजी प्रसार करने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। राष्ट्रीय सरकार को इस दिशा में बेहतर नीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

अंत में भारत सरकार के उस महत्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भरता' के नारे को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जोर लगाना होगा क्योंकि अंततः आज़ादी के सौवें वर्ष में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र की आकांक्षा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। खाद्यान्न उत्पादन से लेकर रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों में आत्मनिर्भरता पाना ही लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान सरकार इस दिशा में पूरे समर्पण से लगी भी है। उम्मीद की जा सकती है कि सौवें वर्ष के सबेरा कुछ अधिक आकर्षक, कुछ अधिक उन्नत और कुछ अधिक विस्तृत होगा।

◆◆◆

आज भारतीय कृषि के घाटे के सौदे को कुछ तथ्यों के माध्यम से बताना चाहें तो भारत में जहाँ एक कृषक श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता मात्र 200 डॉलर के आसपास है, वहीं नार्वे में यह लगभग पाँच गुना और यूएसए में यह बारह गुना से भी अधिक है। इस स्थिति को दूर करने के लिए दीर्घकालिक और स्थायी उपायों पर काम करना होगा।

एसआईपी.

सेहत के लिए नियमित योगा करने जैसा लाभकारी

अधिक जानकारी के लिए, अपने म्यूच्युअल फ़ंड वितरक / पंजीकृत निवेश सलाहकार से संपर्क करें या 73587 12345 पर मिस्ड कॉल दें.

एसआईपी - सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेन्ट प्लान

म्यूच्युअल फ़ंड्स में निवेश करने के लिए, एककालिक अपने ग्राहक को जानिए (KYC) की अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी हेतु https://www.hdfcfund.com/information/key-know-how पर विजिट करें. निवेशकों को केवल रजिस्टर्ड म्यूच्युअल फ़ंड्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिनके विवरण का सत्यापन सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in/intermediaries.html) पर किया जा सकता है. किसी पूछताछ, शिकायत तथा समस्या के समाधान के लिए निवेशक एएमसीज़ तथा/या निवेशक संपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही, अगर निवेशक एएमसीज़ द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट न हों तो https://scores.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. स्कोर्स पोर्टल निवेशकों को सेबी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तथा तत्पश्चात इसकी स्थिति को देखने की सुविधा प्रदान करता है.

An Investor Education Initiative By

HDFC MUTUAL FUND

BHAROSA APNO KA

म्यूच्युअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें.

भारत की भूमिका विश्व गुरु के दायित्व बोध से अनुप्राणित होनी चाहिए

भारत विश्व का एक ऐसा ईमानदार व मानवतावादी देश है जिसने अपने किसी भी पड़ोसी राष्ट्र पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है, किसी की एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। भारत की संस्कृति एवं संस्कार में न्याय, निष्पक्षता एवं आचरण के प्रति निर्मलता कूट-कूट कर भरी हुई है।

कृपाशंकर तिवारी
संस्थापक संपादक, अभ्युदय वात्सल्यम्

भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए और हम भारतीय आज हर्षोल्लास एवं गर्व के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। सम्पूर्ण देश में तिरंगा यात्राएं निकलीं और देश की आन-बान-शान के प्रतीक भारतीय ध्वज को अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ। निश्चित ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने आज तक राष्ट्रीय जन-जीवन के विविध क्षेत्रों में सम्मानजनक एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिन पर हम सन्तोष व्यक्त कर सकते हैं और गर्व कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, टेक्नॉलजी, विज्ञान, कृषि, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है किन्तु स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अभी भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत कुछ करना शेष है। आत्म निर्भरता किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की एक सशक्त, सक्षम व सर्व जन सुलभ आदर्श स्थिति है। आत्मनिर्भरता में ही हमारी विशिष्टता एवं आत्मसम्मान का गौरवपूर्ण भाव एवं स्थिति सन्निहित है। अत:, भारत को अपनी सम्पूर्ण मानवीय शक्ति, सामर्थ्य और संसाधनों का समुचित सदुपयोग करते हुए योजनाबद्ध रूप से आत्म निर्भरता की स्थिति प्राप्त करनी ही होगी। सुखद है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ध्यातव्य है कि 135 करोड़ भारतीयों की सामूहिक चेतना, कर्तव्यबोध, कर्मठता तथा राष्ट्र के प्रति एक सुयोग्य नागरिक के रूप में हमारे समर्पण भाव से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है और भारत का दीर्घकालीन अपेक्षित स्वप्न साकार हो सकता है। भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार राष्ट्र है, जिसने पौराणिक काल से ही सम्पूर्ण विश्व को अध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कला एवं मानवता का पाठ पढ़ाया है, शिक्षा प्रदान की है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की महान भावना से अनुप्राणित भारत का राष्ट्रीय चरित्र सदैव विश्व परिवार के लिए आदर्श, प्रेरक एवं प्रकाशक रहा है। प्रेम, अहिंसा, शांति, सद्भाव, करुणा, दया, क्षमा, शील, परोपकार, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, पारस्परिक सहयोग आदि सद्गुण भारत के राष्ट्रीय चरित्र के आभूषण हैं। भारत की कथनी और करनी में सदैव एकरूपता की स्थिति बनी रही है। भारत विश्व का एक ऐसा ईमानदार व मानवतावादी देश है जिसने अपने किसी भी पड़ोसी राष्ट्र पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है, किसी की एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। भारत की संस्कृति एवं संस्कार में न्याय, निष्पक्षता एवं आचरण के प्रति निर्मलता कूट-कूट कर भरी हुई है। हमारी सनातन संस्कृति विश्व की महानतम् संस्कृति है जो आत्मज्ञान, प्रेम, करुणा, दया तथा सेवा भावना पर आधारित है।

भारतीय दर्शन, चिन्तन, अवधारणा, विचार एवं आचरण के आलोक में सम्पूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है। जिस प्रकार परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक प्रेम, अपनत्व, त्याग एवं सहयोग की भावना होती है, उसी प्रकार विश्व रूपी परिवार में भी भारत अपनी भावना एवं आचरण रखता है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम्, सेवा परमोधर्मः, सत्यमेव जयते तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को आत्मसात कर वैश्विक आचरण करने वाला एक महान राष्ट्र है। भारत में सदैव चरित्र की ही पूजा, उपासना एवं वंदना की गई है। भारत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योग योगेश्वर भगवान कृष्ण जैसे पूर्णावतारों की अवतरण भूमि है, महान ऋषियों-महर्षियों की तपः स्थली है तथा देश-दुनिया का गौरव बढ़ाने वाले लोकसेवी महापुरुषों की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। राम, कृष्ण के महान आचरण और दिव्य मानव कल्याणकारी संदेश को आत्मसात् कर जीने वाली भारतीय सनातन संस्कृति भी धन्य है, जिसमें मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, पशु, पक्षी, पत्थर, नदी, समुद्र, वृक्ष आदि की भी पूजा की जाती है और उनमें भी भगवान के दर्शन किए जाते हैं।

भारत का आध्यात्मिक-सांस्कृतिक ज्ञान का क्षेत्र अनुपम एवं विशाल है, जो स्वयं में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का दर्शन कराता है और ब्रह्माण्ड के कण-कण में स्वयं का दर्शन कराता है। अर्थात् भगवान सम्पूर्ण बह्मांड के कण-कण में व्याप्त हैं और सम्पूर्ण बह्मांड भगवान में स्थित है। भारत में पौराणिक काल से ही ज्ञान-विज्ञान एवं अध्यात्म की विपुल सम्पदा का अक्षय भण्डार रहा है जो आज भी स्वयं भारत और सम्पूर्ण विश्व के लिए उतना ही उपयोगी, महत्वपूर्ण, सार्थक तथा जीवन को धन्यता प्रदान करने वाला है, जिनता पूर्व काल में था। त्रिकाल में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ रहा है।

ज्ञान के प्रकाश में ही समस्त की प्राप्ति एवं सर्व अभीष्ट की सिद्धि सम्भव है। इसीलिए ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सांसारिक धन-सम्पदा का सदुपयोग भी ज्ञान के माध्यम से ही किया जा सकता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी का उद्गम स्थल भारत ही है। भारत को पतित पावनी माँ गंगा की अलौकिक गोद प्राप्त है, जिसमें संसार के प्राणिमात्र को पवित्र करने और सद्गति प्रदान करने की शक्ति है। भारत के वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों में अपार ज्ञान-सम्पदा है जो आज भी मानव कल्याणकारी है तथा जगत का वास्तविक कल्याण विकास करने में समर्थ है। भारत का गौरवशाली अतीत सत्य, प्रेम, दान, न्याय, मैत्री एवं त्याग के असंख्य प्रेरणाप्रदायी उदाहरणों से परिपूर्ण है, सुशोभित है। भारत में प्रत्येक काल में उत्कृष्ट प्रतिभाओं, दिव्य विभूतियों एवं महापुरुषों ने अपने कर्म प्रकाश से राष्ट्र एवं सम्पूर्ण विश्व के कल्याणार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है।

राम, कृष्ण के साथ ही साथ यह सत्यवादी-महादानी राजा हरिश्चन्द्र, महादानी दधीचि, महान त्यागी शिबि, भक्त शिरोमणि प्रहलाद और भक्तराज ध्रुव, जगत-जननी माँ सीता, महासती अनुसूया, सती सावित्री, आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, भक्त शिरोमणि संत तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, रसखान, भक्त मीराबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल, चन्द्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह जैसे महान विभूतियों एवं अमर पुत्रों की पावन भूमि है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। उपरोक्त महान विभूतियों का दिव्य प्रकाश भारतीय राष्ट्रीय चरित्र में आज भी विद्यमान है और आज भी भारत को सत्य, ज्ञान, तप-त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करते हैं।

भारत में आगामी पच्चीस वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशहाली जन-जन को प्राप्त हो, विश्व मंच पर भारत और अधिक तेजस्विता तथा दृढता के साथ अपनी महत्वपूर्ण वैश्विक कल्याणकारी भूमिका निभाए, यह हम सबकी शुभकामना है।

अतः, भारत को अपने महिमामय स्वरूप में स्थित होकर सम्पूर्ण शक्ति के साथ अपने तथा विश्व के व्यापक हित में एक और ऐतिहासिक भूमिका के निर्वहन के प्रति गम्भीरतम् प्रयास करने होंगे, जो **विश्व गुरु** के दायित्व बोध से अनुप्राणित होनी चाहिए।

◆◆◆

मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को 'गुजरात मॉडल' के रूप में प्रस्तुत कर लगातार दो लोकसभा चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी लगभग अजेय रहे हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह किसी अचरज से कम नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता से देश के सर्वोच्च नेता की यात्रा प्रेरक भी है और राजनीतिज्ञों के लिए गुत्थी उलझाने वाला भी।

नरेन्द्र मोदी

कालजयी राजनीतिक जीवन यात्रा

– सन्नी कुमार

वर्तमान के चश्मे से देखें तो नरेन्द्र मोदी एक चमत्कार की तरह दिखते हैं। इनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह उभरता है कि जिनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो– चुनाव जीतना और देश के लिए विषय तय करना, जो जनता से जुड़ने का हुनर रखता है और विपक्ष को पटखनी देने की क्षमता भी। एक लंबी और सफल राजनीतिक विरासत जब मूर्त रूप लेती है तो ऐसी शख्सियत निर्मित होती है। हालाँकि, आज के इस जादू से थोड़ी दूर हटें तो नरेन्द्र मोदी की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। खासकर, जिस विपक्ष से उनकी प्रतिस्पर्धा थी/है उसकी तुलना में नरेन्द्र मोदी के पास कुछ भी नहीं था। आइये, एकदम संक्षेप में उस घटनाक्रम को जानते हैं कि "कुछ नहीं से सब कुछ" की यह यात्रा कैसी रही।

आजादी के तीन बरस बीत चुके थे, जब 17 सितम्बर को नरेन्द्र मोदी का जन्म औद्योगिक राज्य गुजरात में हुआ। जगह थी वडनगर। एक बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि में नरेन्द्र मोदी का

लालन-पालन हुआ और यही वजह है कि संघर्षों के सहारे एक बेहतर जीवन बुनने की उनकी जिजीविषा उनके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत अंग बन गयी। कालांतर में उनकी रुचि राजनीति में बढ़ी और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। यह संयोग 70 के दशक में कभी घटित हुआ था। आने वाले कुछ वर्षों में भाजपा का भी गठन होना था और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर भाजपा तक आ पहुँचा। पहले गुजरात राज्य में संगठन को मजबूत करने, राज्य में चुनाव जिताकर सरकार बनाने में भूमिका निभाने और फिर केंद्रीय संगठन में आने की एक उत्तरोत्तर बढ़ती

नरेन्द्र मोदी आज केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं हैं बल्कि उन्होंने भविष्य के भारत की ठोस बुनियाद भी तय कर दी है।

राजनीतिक हैसियत के साथ मोदी अपना कद ऊँचा करते गए। और फिर 21वीं सदी की शुरुआत में ही वो एक विभाजक समय भी आ गया, जिसने मोदी, भाजपा और भारतीय राजनीति का भाग्य उसी समय तय कर दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को 'गुजरात मॉडल' के रूप में प्रस्तुत कर लगातार दो लोकसभा चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी लगभग अजेय रहे हैं। अगर, प्रत्यक्ष नेतृत्व की बात करें तो वो अजेय ही रहे हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह किसी अचरज से कम नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता से देश के सर्वोच्च नेता की यात्रा प्रेरक भी है और राजनीतिज्ञों के लिए गुत्थी उलझाने वाला भी। बहरहाल, अब यह देखना अधिक रोचक होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कैसे संभव हो सकी? वो कौन से कारक हैं जो इन्हें अपने प्रतिस्पर्धी नेताओं से अलग बनाते हैं?

वैचारिक स्पष्टता

नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी होने में जो एक बात बुनियादी रूप से कही जा सकती है वो है वैचारिक स्पष्टता। राजनीतिक विचार हो या सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा या फिर आर्थिक नीति, नरेंद्र मोदी शुरू से ही काफी स्पष्ट रहे हैं। और यही वजह है कि वो पूरे आत्मविश्वास से जनता से जुड़े और उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। और, यह वैचारिक स्पष्टता क्या है?

नरेन्द्र मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो अपनी धार्मिक पहचान को लेकर किसी दुविधा में नहीं था। कश्मीर को शेष राष्ट्र से जोड़ने की कसम भी निभाई।

सबसे पहले सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीति में भी संस्कृति के रोचक उपयोग होते रहे हैं, जिनमें सबसे सफल प्रयोग "सांप्रदायिकता–सेकुलरवाद" का है। धर्म के ही उपयोग पर ही दोनों प्रकार की राजनीति टिकी रही, लेकिन एक को सेकुलरवाद कहा गया और दूसरे को सांप्रदायिकता। यहाँ इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि इन दोनों ही विचारों के व्यावहारिक (चुनावी) अनुप्रयोग इनकी सैद्धांतिक निर्मिति से एकदम अलग है। वस्तुतः, भारत में परस्पर विरोधी सांस्कृतिक मूल्यों के कारण पैदा हुई नैतिक असहमतियों का राजनीतिक हल खोजने की कभी कोशिश नहीं हुई। विविधता के नष्ट हो जाने के डर या बहुसंख्यक संस्कृति के हावी हो जाने के भय से यहाँ सामाजिक एकीकरण पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया तथा सार्वभौम नागरिक निर्माण की परियोजना अधूरी ही रह गई। इसके अलावा वैविध्य बनाए रखने के लिए राज्य की तरफ से जो प्रयास हुए उसका एक संदेश यह भी गया कि जानबूझकर बहुसंख्यक की धार्मिक पहचान को बेअसर करने की कोशिश हुई और अल्पसंख्यक को अपनी पहचान धार्मिक रूप से गढ़ने के लिए न केवल छूट दी गई बल्कि प्रोत्साहित भी किया गया। इसी आधार पर हो रही राजनीति को नरेन्द्र मोदी ने बदला और पूरी निर्भीकता से खुद को उस खेमे में प्रस्तुत किया जिसे 'सांप्रदायिक' कहने का चलन है। यानी हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा रखना, उसके प्रतीकों को सम्मान देना, इस समुदाय के आग्रह को राष्ट्रीय विषय बनाना आदि। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर कश्मीर से अनुच्छेद-370 को प्रभावशून्य करने तक की यह यात्रा बहुत स्पष्ट रही है।

वैचारिक स्पष्टता का दूसरा पक्ष राजनीतिक–आर्थिक है। यह स्पष्टता और बेहतर ढंग से उभर सके इसलिए पहले इनकी प्रतिद्वंद्वी वर्तमान कांग्रेस का नजरिया देख लेते हैं। कांग्रेस कभी नेहरू –इंदिरा के समाजवाद के प्रति मोह दर्शाती है तो कभी राव– मनमोहन के पूंजीवाद के लाभ का श्रेय लेना चाहती है। दिलचस्प बात है कि 1990 में उदारवादी – पूंजीवादी व्यवस्था को पुरजोर तरीके से अपनाने में जिस मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका थी, वो नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के पहले दस साल कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करते रहे, किंतु इसके ठीक बाद जिस राहुल गांधी के पास नेतृत्व आया वो समाजवाद का झंडा बुलंद करने की कोशिश करने लगे। चाहे संसद में नाम लेकर उद्योगपतियों की आलोचना करना हो या प्रधानमंत्री पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसना हो, राहुल गांधी खुलकर दूसरे खेमे में होने को दर्शाते रहे। वो भी तब जब राहुल जिस 'युवा कांग्रेस' के सहारे पार्टी की सूरत बदलना चाह रहे थे, उनमें से अधिकांश समाजवादी प्राप्ति की मरीचिका से ऊबे हुए लगते थे। इसके विपरीत नरेन्द्र मोदी एकदम स्पष्ट नजर आए। इन्होंने जनकल्याणकारी राज्य की धारणा से डिगे बिना समाजवादी नीति से चिपके रहने के संकोच को त्याग दिया। नए समय के अनुकूल आर्थिक नीति जिसमें न्यूनतम शासन के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम, विदेशी निवेश के प्रति आकर्षण, विनिवेश, नागरिक उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने जैसी नीतियों के सहारे मोदी आगे बढ़े। ये सभी परंपरागत समाजवादी नीति से स्पष्ट विचलन के संकेत हैं। वस्तुतः नरेन्द्र मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो अपनी धार्मिक पहचान को लेकर किसी दुविधा में नहीं था। कश्मीर को शेष राष्ट्र से जोड़ने की कसम भी निभाई। न्यूजरूम से मंत्री बनाने का चलन खत्म किया, राजनीति को चंद अभिजनों के इशारे पर निर्देशित होने की परिपाटी मिटाई, देश को नई तकनीक के प्रति सहज होने का अभ्यास कराया,

नए समय के अनुकूल आर्थिक नीति जिसमें न्यूनतम शासन के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम, विदेशी निवेश के प्रति आकर्षण, विनिवेश, नागरिक उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने जैसी नीतियों के सहारे मोदी आगे बढ़े।

जन धन से लेकर उज्ज्वला तक तमाम ऐसे छोटे दिखने वाले बड़े उपाय किए।

नेतृत्व से आखिर हमारी क्या अपेक्षाएँ होती हैं? यही न कि वो कठिन समय में न केवल उचित निर्णय ले बल्कि दृढ़तापूर्वक डटे रहने का कौशल भी दिखाए! उसकी भंगिमा सकारात्मक हो। उसकी भाषा संयत हो। उसको साथ खड़ा होना आता हो। जोखिम लेने की प्रवृत्ति हो। जिसकी उपस्थिति उत्साहित करे और जो हार जीत को अपने बूते स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। किसी संगठन का लीडर जितना कुशल, परिश्रमी और जोखिम उठाने वाला होता है वह संगठन भी उतना ही मजबूत हो जाता है। तमाम व्यावहारिक बातों के बावजूद नेतृत्व का एक अदृश्य प्रभाव होता है। अच्छे लीडर इस प्रभाव को और सघन कर देते हैं। और इस कसौटी पर देखें तो नरेन्द्र मोदी एकदम खरे उतरते हैं। देश की केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने की लगातार कोशिशों के बाद भी ज्यादातर बार असफल ही रहे संगठन को जीत के लिए तैयार करना कोई साधारण बात नहीं। भाजपा भी 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद काफी कुछ ऐसी ही निराशा महसूस कर रही थी। ऐसे में नरेन्द्र मोदी ने संगठन को जीत के लिए तैयार किया और कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास से भर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने हर बार जीत–

हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। चुनावी कोशिशों से अलग देखें तो उन्होंने राज्य के अन्य मूलभूत इकाइयों को भी राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ा, चाहे वह इसरो का कोई अंतरिक्ष प्रयोग हो या फिर कोई सैन्य अभियान। यहाँ इस प्रसंग का जिक्र करना समीचीन होगा कि सीमा विवाद के समय प्रधानमंत्री के लेह जाने से कोई चमत्कार हो गया हो या फिर उससे सीमा तनाव क्षणभर में दूर हो गया हो, ऐसा नहीं है। किंतु, इन सब के बावजूद इस उपस्थिति में सीमा के दोनों पार के लिए एक संदेश था। सरहद के अंतर से संदेश की

ग्राह्यता में अंतर जरूर आएगा लेकिन जो एक बात एकदम स्पष्ट थी वो यह कि प्रधानमंत्री अपने नागरिकों और सैनिकों के पक्ष में मुस्तैद है। दिल्ली और सेना के बीच एक दूरी होती है और वो होनी भी चाहिए, लेकिन एक सेतु भी हो जो एक दूसरे को जोड़े रखे। सिर्फ औपचारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सेना का मनोबल निश्चय ही बढ़ा होगा। निर्णय लेने में मस्तिष्क और जुड़ने में हृदय का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों अपनी – अपनी जगह कायम रहे तो कोई भी दौड़ जीती जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही नेतृत्व देश को दिया है।

नरेंद्र मोदी ने भविष्य के भारत की ठोस बुनियाद तय कर दी है।

वस्तुत: नरेन्द्र मोदी आज केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं हैं बल्कि उन्होंने भविष्य के भारत की ठोस बुनियाद भी तय कर दी है। "भारत गावों में बसता है" जैसे लोकप्रिय मुहावरे को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, नई तकनीकी दुनिया से कदमताल करने के लिए डिजिटल इंडिया का सपना, भ्रष्टाचार रहित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हितों को पूरे आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने जैसे अनेक प्रयास हैं, जिनकी परिधि में आने वाला समय आकार लेगा। यह एक ऐसा समय है जब नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले समय को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और यही इनके कद को और बड़ा कर देता है।

◆◆◆

डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने वाले प्रधानमंत्री

- राजीव चंद्रशेखर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलैस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत किया जा सके।

वर्तमान में हम औद्योगिक क्रांति के चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनी मुख्य भूमिका में है। एक बेहतर संचार तंत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से आज पूरी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। ऐसे में आज किसी भी देश की वास्तविक प्रगति के लिए आवश्यक है कि वह तकनीकी रूप से सहज,सक्षम और उन्नत हो। समय की इस अपरिहार्य आवश्यकता को अगर किसी व्यक्ति ने भली-भांति समझा है तो वह हैं हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी। उम्र के इस पड़ाव में आकर भी तकनीक के प्रति जो लगाव व सहजता हमारे प्रधानमंत्री जी में है वह वास्तविक मायनों में एक बेहतर नेतृत्वकर्ता में ही हो सकती है। वे प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग की बात करते हुए अक्सर सरकार के उन कदमों की ओर इशारा करते हैं जिसमें अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने से लेकर समाज में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना शामिल है। उदाहरण के लिए नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक पर्यवेक्षण निकाय की स्थापना, उमंग और डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पीएलआई स्कीम, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि पाषाण युग से औद्योगिक क्रांति तक

समग्र रूप से कहा जाए तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था समय की मांग थी जिसे मोदी जी ने ना केवल बखूबी समझा बल्कि उसे आम जनमानस के बीच प्रचारित व प्रसारित भी किया।

आने में जहां लाखों वर्ष लग गए वहीं संचार क्रांति महज पिछले 200 वर्षों का परिणाम है जबकि डिजिटल क्रांति ने यह दूरी कुछ ही वर्षों में पूरी कर ली।

बदलाव की कहानी

प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल क्रांति ने आज हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। आज जो भी देश डिजिटल साक्षरता में जितना पीछे हैं वह प्रगति की रफ्तार में भी उतना ही धीमा है। इस तथ्य को भलीभांति समझते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैशलैस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत किया जा सके।

अब अगर बात डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की करते हैं तो यह मूलत: तीन दृष्टिकोण पर आधारित है –डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, मांग आधारित ई गवर्नेंस सेवा और डिजिटल साक्षरता। यह कार्यक्रम नौ स्तंभों पर टिका हुआ है जो हैं ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुंच,पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई–गवर्नेंस, ई–क्रांति:. NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण,रोजगार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी और अगली हार्वेस्ट प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को देश की राजधानी से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण में 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की पहल की है। साथ ही देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ढाई लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है जिसने भारत के निर्धनों, हाशिए पर खड़े समूहों ,दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है। इसी पहल का परिणाम है कि आज लोग लोग घर से काम करने, कैशलेस भुगतान पाने, छात्र ऑनलाइन शिक्षा पाने, मरीज टेली–कंसल्टेशन से डॉक्टरी सलाह लेने और किसान सीधे अपने बैंक खाते में पीएम–किसान जैसी योजना का लाभ लेने में सक्षम हो पाए हैं। यहीं पर हमें ई–क्रांति जिसे अन्य रूप में हम राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना 2.0 के नाम से भी जानते हैं, की बात कर लेना भी ज्यादा समीचीन होगा।

इस योजना का उद्देश्य परिवर्तनशील और परिणामोन्मुखी ई–गवर्नेंस पहलों को प्रोत्साहन देना, एकीकृत सेवाएं प्रदान करना तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग व नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना आदि शामिल है। इसके अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी जैसी बहु–संस्थागत परियोजना का भी समर्थन किया है जिसके माध्यम से शासन,बैंकिंग,वित्त,साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना व उनका विकास करना शामिल है। इसी तरह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नैसकॉम की साझीदारी से फ्यूचर स्किल प्लेटफार्म को लांच किया गया है जो ब्लॉकचेन,कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित दस उभरती

हुई तकनीकों पर केंद्रित है।

कहने का अर्थ यह है कि माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में काम करते हुए प्रत्येक विभाग आधुनिक सूचना व प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग व समन्वयन करते हुए इस क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात कर रहा है। यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि भले ही सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रारंभ किसी भी सरकार के कार्यकाल में हुआ हो लेकिन उसे निरंतर नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय निश्चित रूप से मोदी जी को जाता है। यहां हम कुछ मुद्दों पर गौर करें तो ये बातें और भी स्पष्ट हो जाती हैं।

तकनीक के सहारे गरीबों का भला करने की नीति

मोदी जी के आने से पहले अधिकांश भारतीय न्यूनतम बैंकिंग सेवाओं से भी वंचित थे। जो इन सेवाओं का लाभ उठा भी रहे थे उन्हें इसके लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी तो और दूर की कौड़ी हुआ करती थी। लेकिन, मोदी जी के आगमन के बाद जहां इन कठिनाइयों ने सहजता का रूप लेना शुरू किया वहीं कैशलैस इकोनॉमी भी परिकल्पना से निकलकर यथार्थ के धरातल पर अवतरित हुई। अपने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही महीनों बाद यानी 15 अगस्त, 2014 को मोदी जी ने विशाल जन–धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की जिसके माध्यम से करोड़ों भारतीयों के बैंक खाते खुले और वे औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने में समर्थ हो सके। हालांकि, शुरुआत में विरोधियों द्वारा इन खातों में जमा हुई न्यून राशि को आधार बनाकर मोदी सरकार का उपहास भी उड़ाया गया किंतु कोविड–19 महामारी के दौरान जब आवागमन और कामकाज पूरी तरीके से ठप्प पड़ गए थे तब इन्हीं बैंक खातों में विभिन्न माध्यमों और लोगों द्वारा अंतरित की गई राशि ने निर्णायक भूमिका अदा की। ठीक यही बात मोदी जी के वृहद सपने कैशलेस अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। एक पल के लिए हम समय में पीछे जाएं और यह विचार करें कि अगर कोविड–19 के दौरान हमारे पास भुगतान का कैशलेस विकल्प नहीं होता तो हम किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाते। दुनिया हमारा उपहास उड़ाती और हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाती। किंतु मोदी जी की दूरदृष्टि की बदौलत हम उस नारकीय अवस्था में नहीं गए। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही जिस तरह से उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र के विकास व विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित किया वह स्वयं में काबिले तारीफ है।

आज बैंकिंग,पेंशन, बीमा और सब्सिडी आदि का निपटारा चंद मिनटों में ऑनलाइन हो जा रहा है। एक बड़े दुकानदार से लेकर साधारण फेरीवाले तक के पास यूपीआई के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा है। बच्चे घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसान टेलीविजन अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों से फसलों और मौसम की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके लिए पहले घर के बाहर जाना पड़ता था किंतु अब नहीं। इसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को तो हुआ ही साथ ही उन समूहों को भी हुआ जो सरकारी कार्यालयों तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं थे।

समग्र रूप से कहा जाए तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था समय की मांग थी जिसे मोदी जी ने ना केवल बखूबी समझा बल्कि उसे आम जनमानस के बीच प्रचारित व प्रसारित भी किया। भारत जैसे विकासशील और विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां अभी भी व्यापक पैमाने पर गरीबी,भुखमरी व कुपोषण पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है वहां अत्याधुनिक संचार व तकनीकी व्यवस्था का विकास करना काफी दुरूह एवं जटिल कार्य था। इसके लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जिनके पास भविष्य को लेकर एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण हो और जो वैश्विक परिवर्तनों के प्रति पहले से ही सचेत एवं तैयार हो। मोदी जी ने इन बातों का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रयासों एवं माध्यमों से लगातार जनमानस को इन परिवर्तनों को अपनाने के प्रति जागरूक व विवेकशील बनाया और इसी का परिणाम है कि आज हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की कतार में अग्रणी स्थान धारण करते हैं। फिर चाहे वह अंतरिक्ष क्षेत्र हो,साइबर क्षेत्र हो,रक्षा क्षेत्र हो अथवा अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र, हमने कई बार वैश्विक समूहों को भी अपनी अभूतपूर्व प्रगति के माध्यम से अचंभे में डाल दिया है।

(लेखक केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री हैं)

◆◆◆

AJMERA
Built on Trust

100 acres interconnected, integrated new age living destination in the heart of Mumbai city

AJMERA
i-LAND
WHERE FUTURE LIVES

WADALA (E)

2,3 & 4 BHK Available

SPRAWLING SPORTS ACADEMY | INDEPENDENT CLUBHOUSES | UPCOMING SCHOOL AND COMMERCIAL AVENUES

Planned by the world renowned New York based architects, Skidmore, Owing & Merrill LLP (SOM), the designers of Dubai's Burj Khalifa

SITE: AJMERA i-LAND, NEXT TO I-MAX BHAKTI PARK, WADALA (E) • E: iland@ajmera.com • W: www.ajmera.com

Visit us to know more or call:
9699 095 095

49 years of fulfilling dreams | 40,000 homes of happiness | 45 million sq. ft. of development • Mumbai | Pune | Bangalore | Ahmedabad | Bahrain

Disclaimer: All the specifications, designs, facilities, dimensions etc. are subject to the approval of the respective authorities. The developers reserve the right to change the specifications or features without any notice or any obligation. Images are for representative purpose only.

Project funded by HDFC ICICI Bank

Follow Ajmera Realty on

सोम प्रकाश

विश्व नेता नरेन्द्र मोदी

आज विश्व मंच पर भारत को एक विशेष दृष्टि से देखा जाने लगा है। भारत के कुशल व प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी स्पष्ट, पारदर्शी एवं विश्व हितैषी विचारधारा एवं कार्यों से न केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित किया बल्कि विश्व समुदाय के लिए नेतृत्व के स्तर पर स्वयं में एक आश्वासन के रूप में सामने आए हैं।

नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को दूरदृष्टि सम्पन्न एवं वीरव्रती भाव से राष्ट्र सेवा करने वाला राष्ट्रीय प्रहरी प्राप्त हुआ है, जो भारत को उसकी गरिमा के अनुरुप योग्य शासन व्यवस्था एवं दिशा देने में सर्वथा सक्षम है।दृढ़ विचार, स्पष्ट लक्ष्य एवं दूरदर्शितापूर्ण सोच का मोदी के महान व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान है।

राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर राष्ट्र नायक के रूप में नरेन्द्र मोदी के अभ्युदय की अनिवार्यता एक निर्विवाद तथ्य सिद्ध हुआ। देश के सुयोग्य, कर्मठ एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की अब तक की सेवाएँ भारत को द्रुतगति से राष्ट्रीय विकास पथ पर अग्रसर करने में न केवल वरदान सिद्ध हो रही हैं अपितु सम्पूर्ण देश में विकास, सुरक्षा, स्वच्छ शासन-व्यवस्था तथा जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से सरकार ने भारतीय जनमानस में एक विश्वास एवं आश्वस्ति के भाव का निर्माण करने में भी सफलता प्राप्त की है। नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को दूरदृष्टि सम्पन्न एवं वीरव्रती भाव से राष्ट्र सेवा करने वाला राष्ट्रीय प्रहरी प्राप्त हुआ है, जो भारत को उसकी गरिमा के अनुरूप योग्य शासन व्यवस्था एवं दिशा देने में सर्वथा सक्षम है। दृढ़ विचार, स्पष्ट लक्ष्य एवं दूरदर्शितापूर्ण सोच का मोदी के महान व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान है। लक्ष्य के प्रति सम्पूर्णतया समर्पण, प्रखर पुरुषार्थ तथा अनथक परिश्रम उनके व्यक्तित्व का महनीय गुण है जो विरले लोगों में ही पाया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके उत्कट प्रयास हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए माँ भारती की सेवा में सर्वस्व समर्पित करने हेतु महान प्रेरणा प्रदान करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी सहित करोड़ों देशवासियों को अपने राष्ट्र नायक पर गर्व है और विश्वास है कि प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व भारत का सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतया समर्थ है, सुयोग्य है। दीर्घावधि के बाद देश को ऐसा राष्ट्र नायक मिला है जैसा देश को

चाहिए था, जैसी देशवासियों की अपेक्षा थी। नरेन्द्र मोदी के विश्वसनीय एवं चमत्कारिक नेतृत्व में भाजपा को दूसरी बार प्राप्त हुआ प्रचंड जनादेश मोदी जी के सुयोग्य नेतृत्व के प्रति देश के उत्कट विश्वास और लोकप्रियता का परिचायक है। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कर्मठ सेवाएँ भारत को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्रगति से अग्रसर करते हुए शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की एक भी छोटी या बड़ी घटना नहीं हुई, कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा कैसे संभव हुआ? वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार की पारदर्शी नीतियाँ, जवाबदेह व ईमानदार शासन, राष्ट्रीय हितों के प्रति पूर्णतया समर्पण की उत्कट भावना और सबका साथ- सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार की सुव्यवस्थित व कर्मठ कार्य प्रणाली ही सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना सम्भव हुआ। नरेन्द्र मोदी के विलक्षण नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति अपेक्षानुरूप सुदृढ़ हुई है और आज भारत को विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा है।

मोदी सरकार की अनेक राष्ट्र कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाएँ राष्ट्रीय जनजीवन को खुशहाल बनाने के साथ- साथ आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक रूप से परिवर्तन ला रही हैं, सुधार ला रही हैं, देश को सुदृढ़ बना रही हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्र कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, डिजिटल इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, आदर्श सांसद ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, अटल पेंशन योजना तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश का चहुंमुखी विकास करने का गंभीर प्रयास कर रही है।

आज विश्व मंच पर भारत को एक विशेष दृष्टि से देखा जाने लगा है। भारत के कुशल व प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी स्पष्ट, पारदर्शी एवं विश्व हितैषी विचारधारा एवं कार्यों से न केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित किया बल्कि विश्व समुदाय के लिए नेतृत्व के स्तर पर स्वयं में एक आश्वासन के रूप में सामने आए हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब भी किसी अन्य देश में जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से अधिक विश्वनेता प्रतीत होते हैं। डोकलाम मुद्दे को सुलझाना उनकी कूटनीतिक एवं राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचायक है। भारत विश्व गुरू रहा है और वसुधैव कुटुम्बकम् की महान भावना हमारी सनातन संस्कृति एवं विश्व धर्म रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री की विलक्षण नेतृत्व क्षमता- दृष्टि-शैली को देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि भारत वैश्विक जन - जीवन में एक बार फिर अपने प्राचीन गुरुत्तर दायित्व के निर्वहन हेतु तैयार है।

(लेखक केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री हैं)

◆◆◆

Our learning is best when it teaches humanity but to be proud of learning is the greatest ignorance in the world.

With Best Compliments from

Umesh Gandhi

Builders & Developers

DEEPAK BUILDERS

POONAM BUILDERS

AVON BUILDERS

GEETA BUILDERS

DEEPDHARSHAN BUILDERS PVT. LTD.

JITEN AGRO LAND & FARM PVT. LTD.

SUNCITY LAND & INFRASTRUCTURE PVT.LTD

SUNRISE PARTY HALL

Builders, Developers & Hospitality Business

Office: B/203 Goyal Shopping Arcade, S.V.Road, Borivali (West), Mumbai - 400 092.

Tel No. 022 - 61363636 Fax No. 022 - 61363600

Email :- poonambuilders@gmail.com

प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत की वैश्विक छवि के नए शिल्पकार

नरेन्द्र मोदी

– शिवा तिवारी

आठ वर्ष के ऐतिहासिक कालखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की सफलता और साख के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने जहाँ एक ओर अपनी सफल कूटनीति से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस सरीखे ताकतवर देशों को अपना मुरीद बनाया है वहीं चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर करारी पटकनी दी है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करना अथवा अपने अनुकूल बनाना आसान नहीं होता। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कमाल कर दिखाया है। पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अभी चंद माह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यात्रा कर दोनों देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को मिठास से भर दिया। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर सहमति बनी जो कि संपर्क, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूटान की यात्रा की। तब उन्होंने "भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत" की जरुरत बताकर दोनों देशों के अटूट रिश्तों को सहेजने की कोशिश की। उन्होंने भूटानी संसद के माध्यम से भूटान को भरोसा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। 2019 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली तब बिम्सटेक देशों के नेताओं को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित किया और उसमें भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के छोटे भाई सरीखे नेपाल के साथ संबंधों को नया आयाम दिया है। उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जनकदुलारी मां सीता की पावन जन्मस्थली जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में दर्शन–पूजन कर दोनों देशों की धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की पहल की। तब उन्होंने कहा था कि वह बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्य तीर्थयात्री बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल से निकला यह उद्गार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि नेपाल भारत के दिल में बसता है और भारत उसके सुख–दुख का साथी है। प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक–सांस्कृतिक संबंधों से इतर दोनों देशों की उन्नति के लिए एक नई परिकल्पना 5–टी यानी ट्रेडिशन (परंपरा), ट्रेड (व्यापार), टूरिज्म (पर्यटन), टेक्नोलॉजी (तकनीक), और ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के क्षेत्र में मिलकर काम करने की वकालत की और नेपाल ने भी सहमति जतायी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का भी दिल जीता है और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिल रही है।

पड़ोसी देशों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मध्य एशिया और यूरोप से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू–राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान–प्रदान, यात्राएं, विचार–विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से मध्य एशिया के देशों से व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में भारत को पैठ बनाने में मजबूती मिलेगी। मध्य एशिया से संबंधों की बेहतरी इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के लिए स्वयं को स्थापित करने का बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक प्रयास से मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। याद होगा 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ जायद" से नवाजा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तब प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया था और 'अपने दूसरे घर' आने के लिए आभार जताया। तब प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में व्यापार जगत के प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद स्पष्ट किया और साथ ही भारतीय रूपे कार्ड को भी लांच किया। इस तरह पश्चिम एशिया में यूएई पहला देश बन गया जहां रूपे कार्ड चलता है। सऊदी अरब से भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं।

याद होगा पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दिलाने की भारत की मुहिम को दुनिया भर में मिल रहे समर्थन के बीच फरवरी 2019 में भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज ने भी भारत के साथ कंधा जोड़ने का वादा किया। जबकि यह सच्चाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी निकटता है। वैश्विक मसलों पर अमूमन दोनों का सुर एक जैसा रहता है। लेकिन, इसके बावजूद भी सऊदी अरब का आतंकवाद के मसले पर भारत का समर्थन बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती महत्ता और सकारात्मक कूटनीतिक विजय का ही नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक पहल से मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान,

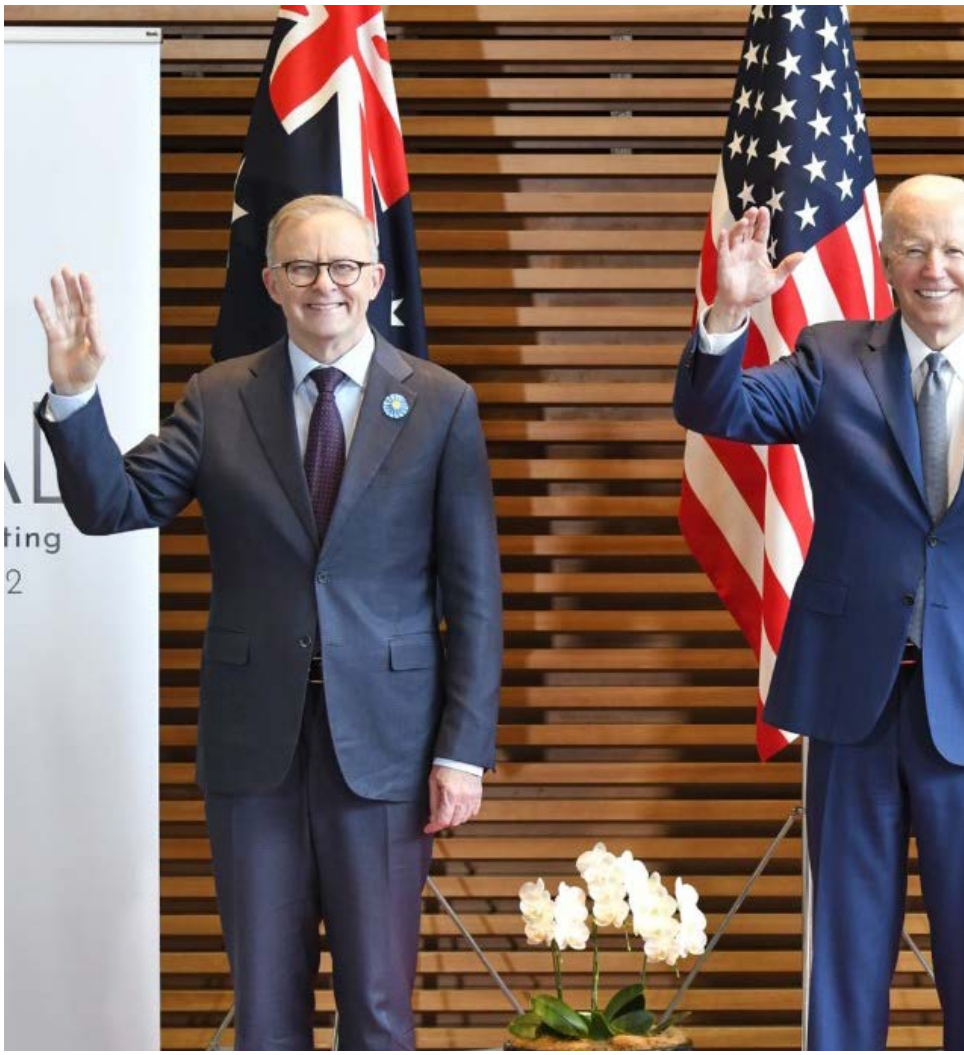

नाइजीरिया, अल्जीरिया, कुवैत, कजाकिस्तान, कतर, मिस्र, बहरीन, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जॉर्डन सरीखे अन्य मुस्लिम देशों से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को पुनर्परिभाषित किया है। दोनों देशों के रिश्ते को स्वर्ग में बनने और धरती पर लागू करने के भावुक विचार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों देश भावनात्मक रूप से एक दूसरे के कितने निकट हैं। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के साथ–साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी रिश्ते परवान चढ़े हैं।

भारत और यूरोपीय संघ 'स्टैंड–अलोन', निवेश संरक्षण पर सहमति के साथ साझा हितों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान जैसे कई अन्य मानवीय मसलों पर सहमति जताते हुए स्वीकार किया कि यह हमारी सामरिक साझेदारी का मूल्य है। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने भारत–यूरोपीय संघ ढांचा 2025 को लेकर तय कार्य बिंदुओं पर आगे बढ़ने तथा टिकाऊ विकास एवं पेरिस समझौता 2030 के एजेंडे पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कूटनीतिक–रणनीतिक धार से दशकों पुराने अमेरिका की पाक नीति को बदलकर रख दिया है। उनकी कूटनीतिक पहल का ही नतीजा है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा भारत के साथ रक्षा संबंध विकसित करने और रक्षा उपकरणों की बिक्री तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अन्य नाटो के सहयोगी देशों के साथ लाने की पहल के तहत द्विदलीय समर्थन वाले बिल को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरिया बढ़ी हैं। पहले अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कितनी निकटता थी, इसी से समझा जा सकता है कि मई, 1965 में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन्सन के निमंत्रण पर वहां की यात्रा का कार्यक्रम बनाया तब उसी समय पाकिस्तान के अयूब खान के दौरे के कार्यक्रम के कारण अमेरिका ने अपना

दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी रिश्ते परवान चढ़े हैं।

निमंत्रण वापस ले लिया। यही नहीं जब भी कभी प्रतिबंधों की बात आयी तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी किसी प्रकार की अमेरिकी सहायता प्रदान करने पर रोक लगाया। यानी तब अमेरिका के पलड़े पर भारत और पाकिस्तान बराबर थे। लेकिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर अमेरिका को उससे न सिर्फ दूर किया है बल्कि अमेरिकी संसद के जरिए भारत और अमेरिका के अपरिहार्य संबंधों को भी निरूपित कर दिया है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी और एमटीसीआर के मसले पर अमेरिका के समर्थन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मानकर चलना चाहिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान को पहले जैसा न तो अमेरिका से करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद मिलने वाला है और न ही कूटनीतिक समर्थन।

मजेदार तथ्य यह भी कि अमेरिका की लाख धौंसपट्टी के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ 40 हजार करोड़ रुपए के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताकर स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यही नहीं भारत ने एस-400 को लेकर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंधों के सवाल पर अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए कह भी चुका है कि भारत का रूस के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकता।

मतलब साफ है कि भारत अमेरिका या रुस के दबाव में अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाला नहीं है। अभी गत माह पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रूस की विक्ट्री डे परेड उत्सव में भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत किया। उस दरम्यान रूस ने चीन की लाख मनाही के बावजूद भी भारत को एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्रतिबद्धता दोहराकर रेखांकित किया कि दोनों देश सदाबहार और भरोसेमंद साथी हैं। गौर करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ते प्रगाढ़ हैं। आमतौर पर भारतीय कालखंड में ऐसा दौर कभी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक दांव के आगे पड़ोसी देश चीन भी घुटने के बल है। उसके लाख विरोध के बावजूद भी भारत मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अब भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका से प्रिडेटर ड्रोन्स को खरीद भी सकेगा। अच्छी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है। क्योंकि मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कतार में हैं। ध्यान देना होगा कि ये वहीं देश हैं जो दक्षिणी चीन सागर में चीन की साम्राज्यवादी नीति से परेशान हैं।

भारत और जापान के एक साथ आने से दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लगाम लगा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सप्लाई एग्रीमेंट (एलईएमओ) ने भी चीन की चिंता बढ़ा दी है। इस समझौते से दोनों देशों के युद्धपोत और फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल तेल भराने एवं अन्य साजो-सामान की आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। इससे चीन खौफजदा है और उसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। चीन इसलिए भी असहज है कि चार देशों के राजनीतिक समूह क्वाड (क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलॉग) के सदस्य देशों-भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी रूख अपना रखे चीन पर नकेल कसना शुरु कर दिया है। मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि चीन को अब अपने हद में रहने की जरूरत है। गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने आठ वर्ष के कालखंड में एक ऐसा ताकतवर भारत गढ़ा है जो हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।

◆◆◆

भारत बदलाव की छोर पर खड़ा है

हर्ष वर्धन श्रृंगला
पूर्व विदेश सचिव
एवं मुख्य समन्वयक, जी-20

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक दूरदर्शी आर्थिक दृष्टिकोण की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटना और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।

2022 का यह वर्ष भारत के लिए बेहद खास है। समूचा देश भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। इस महोत्सव को एक जन-उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जो जन भागीदारी की भावना को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की उपलब्धियां पूरी मानव जाति के लिए उम्मीद की किरण हैं और यह किरण पूरे विश्व को अपने प्रकाश से रोशन करते हुए विकास के रास्ते को गति प्रदान करेगी।

भारत एक उभरता हुआ देश है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत आज बदलाव की छोर पर खड़ा है। भारत ने वर्तमान दौर में खुद को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पुन: स्थापित कर लिया है। यह सराहनीय है। हालांकि, हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत को आने वाले 30 वर्षों में जीडीपी की उच्च दर को ना केवल प्राप्त करना होगा, बल्कि बरकरार भी रखना होगा। इस लंबी और कठिन यात्रा में कई पल ऐसे आएंगे जो मील के पत्थर साबित होंगे।

आज, भारत पारदर्शी और पूर्वानुमेय कर व्यवस्था के साथ दुनिया की सबसे सुलभ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जो कि भारत की आजादी से ले कर अभी तक का सबसे बड़ा कर सुधार है, उसे कार्यान्वित किया। हम रेल, सड़क, बन्दरगाह एवं हवाई जैसी आधारभूत संरचनाओं में तेजी से न केवल सुधार कर रहें हैं बल्कि नव-निमार्ण में भी हम काफी अग्रसर हैं। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना जैसे विश्व-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम कर रहे हैं।

हम वैश्विक हितों के साथ चलने वाले देश का हिस्सा हैं। प्रवासी भारतीयों का भी विश्व में बोलबाला है, जिनकी संख्या न केवल सबसे अधिक है बल्कि उनकी योग्यता भी बेहतरीन है। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा भौतिक सुख, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया भर के सर्विस सेक्टर का पावर हाउस है। हम दुनिया को सीमा रहित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें सभी बाज़ार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में

> भारत में सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक, आयुष्मान भारत की शुरुआत की है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। विदेशी निवेश के लिए आज भारत पहली पसंद है।

भारत ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में काफी बदलाव करते हुए इसे उदार किया, जिसके तहत अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया। कृषि क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण,फार्मा जैसे

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, सार्वभौमिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैशलेस आर्थिक लेनदेन को बढ़ावा देने वाले माध्यमों के जरिए एक मजबूत ज्ञान अर्थतंत्र का निर्माण कर रहा है।

कई क्षेत्रों को जोड़ता है, का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं को और भी अलग-अलग सेक्टर्स के लिए शुरू किया जाएगा।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, सार्वभौमिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैशलेस आर्थिक लेनदेन को बढ़ावा देने वाले माध्यमों के जरिए एक मजबूत ज्ञान अर्थतंत्र का निर्माण कर रहा है। JAM त्रिकोण यानी- **जनधन:** दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल; **आधार:** दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक परियोजना; **मोबाइल कनेक्टिविटी:** मौजूदा सरकार द्वारा त्वरित रूप से प्रसारित, वर्तमान सरकार की नीतियों का परिणाम है, जिसके माध्यम से भारत में फिनटेक (फाइनेंस और टेक्नॉलिजी) क्रांति का मंच दृढ़ता से तैयार हो रहा है।

हाल ही की वैश्विक महामारी ने हमारा ध्यान अपनी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ओर खींचा है। भारत में सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक, आयुष्मान भारत की शुरुआत की है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को अच्छी एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा डिजिटल माध्यम से मुहैया करवाना है। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र, आज 22 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि के साथ निवेश एवं संयुक्त उपक्रम के लिए बहुत ही आशाजनक क्षेत्र बना हुआ है।

देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा को विकसित करने पर जोर दिया है। इसी प्रयास को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड का नारा दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की सफलता वैश्विक चर्चा का हिस्सा है। किंतु एक सत्य यह भी है कि आने वाले कुछ समय तक भारत की ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य माध्यम पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत एवं हाइड्रो पॉवर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्रिपल-पी या प्रो-प्लैनेट पीपल के वैश्विक आंदोलन द्वारा संचालित सतत पोषणीय जीवन और उपभोग पैटर्न के माध्यम से पर्यावरण के लिए लाइफ या लाइफस्टाइल के संदेश पर भी जोर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बनाई गयी कई प्रमुख नीतियां

जनकल्याण को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई हैं। स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा जैसी योजनाओं पर अधिक जोर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए रोजगार सृजन बढ़ा रहा है, आधार के जरिए डीबीटी माध्यम से 110 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर, पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

स्टार्ट-अप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाएं इनोवेशन और नव-उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही हैं। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के 100 से अधिक प्रमुख शहर आधुनिक तकनीक, बेहतरीन कार्यशीलता और सतत विकास के तहत विकसित किए जाएं। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय विकास को सक्षम बनाना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना है जो नागरिकों के जीवन में सुगमता ला सके।

यदि युवाओं को कौशल और शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया गया तो वे हमारे विकास की धुरी बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्किल इंडिया अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य इस वर्ष के अंत तक 40 करोड़ लोगों को कौशल और ट्रेनिंग देना है। अब यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम अपने युवाओं के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर के दें जिसमें उनकी प्रगति हो और वे देश के भविष्य में बेहतरीन रूप से योगदान देने में सक्षम हों। भारत को कौशल, पैमाने और गति द्वारा संचालित विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस कार्य पर भारत सरकार का विशेष जोर है।

इस उद्देश्य से सरकार, देश में फैले डेडिकेटेड फ्रेट और औद्योगिक गलियारों के साथ, विश्व-स्तरीय निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर रही है। इसके अलावा, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार प्रक्रियाओं को सरल बना रही है और लेनदेन के समय और लागत को कम करने के लिए व्यापार के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। इसके तहत पीएम गतिशक्ति योजना, मल्टी-मोडल दृष्टिकोण के तालमेल से लाभ ग्रहण करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए बड़े सार्वजनिक निवेश का मार्गदर्शन करेगी।

स्टार्ट-अप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाएं इनोवेशन और नव-उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही हैं। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के 100 से अधिक प्रमुख शहर आधुनिक तकनीक, बेहतरीन कार्यशीलता और सतत विकास के तहत विकसित किए जाएं।

हालाँकि, हम नैतिक शून्यता में नहीं रह रहे हैं। दुनिया कोविड -19 के परिणामों और वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति से जूझ रही है जिसने अंतरराष्ट्रीय वातावरण को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक दूरदर्शी आर्थिक दृष्टिकोण की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटना और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। अभियान के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए लगभग 270 बिलियन अमरीकी डालर (20 लाख करोड़ रुपये) के प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त वेग देना और देश के कमजोर तबके को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। महामारी की पूरी अवधि में, सरकार ने हमारे 80 करोड़ नागरिकों को लगातार खाद्य सहायता प्रदान की है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत पांच स्तंभों पर खड़ा है: अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित हमारी प्रणाली, जनसांख्यिकी, और मांग। आत्मनिर्भर भारत की सफलता, इन पांचों स्तंभों के सुचारु

एकीकरण और इन्हें आत्मसात करने पर ही मुख्य तौर पर निर्भर करती है।

भारत की उम्मीद केवल भौतिक विकास की नहीं हैं। भारत ने एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई है जो मानव-केंद्रित है। हमने अपनी प्रगति के जटिल सफर के अनुभवों को साझा करने के लिए पार्टनर देशों के साथ मिलकर काम किया है। हमने प्रशांत से अटलांटिक तक फैले भौगोलिक क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाए हैं। हमने कोरोना महामारी के दौरान अपने कई मित्र देशों और सहभागी देशों की सहायता की है। भारत ने अपनी सुरक्षा का साया हमेशा उपलब्ध कराया है।

महामारी की शुरुआती चरण से ही, भारत अपने अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत कोविड-19 की आपदा को अवसर में बदलने में सक्षम हुआ। कोविड -19 महामारी पर चर्चा के लिए सऊदी अरब द्वारा बुलाई गई G-20 के असाधारण शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि कोविड की

आपदा ने अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों की कमियों को सामने लाया है। आर्थिक प्रगति के विशुद्ध अजेंडा के बजाए, पीएम मोदी ने कोविड के बाद की दुनिया में निष्पक्षता, समानता और मानवीय मूल्यों को रेखांकित करती मानव-केंद्रित वैश्वीकरण की नई अवधारणा का आह्वान किया। मानवता को वैश्विक समृद्धि और सहयोग के केंद्र में रखने के प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य तीव्रता से किया।

भारत दुनिया भर के देशों को दवाईयों और कोविड टीकों की आपूर्ति करके दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर कायम रहा। अपने इस प्रयास में देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री की भारत-निर्मित वैक्सीन को किफायती बनाने और संपूर्ण मानवता तक इसकी पहुंच सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया।

हम प्रधानमंत्री के एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य की धारणा को मानते हैं। हमने अपने पड़ोसी देशों के लिए क्लिनिकल परीक्षण और क्लिनिकल प्रैक्टिसेज में क्षमता विकसित करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं।

पिछले एक दशक में भारत की दो-तिहाई से अधिक ऋण सहायता अफ्रीकी देशों को प्रदान की गई है। भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका और अन्य विकासशील क्षेत्रों के देशों को बुनियादी ढांचे के विकास और संस्था निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। भारत हर वर्ष विकास सम्बन्धित साझेदारी गतिविधियों पर तकरीबन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता है। अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के जरिए, भारत ने 47 संस्थानों द्वारा संचालित विविध विषयों में 161 देशों के लगभग 10,000 व्यक्तियों को सालाना प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अन्य विकासशील देशों के छात्रों को 2,300 छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। भारत अपने साथी विकासशील देशों को जो कुछ सहायता प्रदान करता है, उसमें अपनी क्षमताओं को साझा करना और आपदा-जोखिम में कमी के लिए रिमोट-सेंसिंग और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्षमता-निर्माण समर्थन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद की दुनिया में मानव कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए वैश्वीकरण को फिर से उन्मुख करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री जी ने भारत द्वारा प्रारंभ किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या आपदा-प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को रेखांकित करते हुए बताया कि इन योजनाओं का मानव-केन्द्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करने में अहम योगदान है।

प्रधान मंत्री ने अगले 25 वर्षों को भारत 75 से भारत 100 तक संदर्भित किया है, जिसे 100वीं वर्षगांठ तक अमृत काल कहा जाएगा। यह भारत के 130 करोड़ लोगों के सामूहिक प्रयासों का समय है ताकि भारत अपनी पूरी क्षमता का उपयोग देश के समग्र विकास के लिए कर सके।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों के दिए संदेश में भारत की लोकतांत्रिक साख पर बात करते हुए पीएम मोदी के इस दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने भारत के समृद्ध लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र ने मौजूदा दौर में न केवल अपनी जड़े मिट्टी में जमाईं, बल्कि उन जड़ों को समृद्ध भी किया है। भारत एक जीवंत और लचीला लोकतंत्र है जो अमृत काल में प्रवेश करते ही अगले 25 वर्षों में अपनी विकास की गाथा को स्वर्ण अक्षरो में अंकित करेगा।

भारत आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक, G20 की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है, हम उदाहरण से नेतृत्व करना चाहते हैं। भारत ने न केवल कोविड -19 महामारी और अन्य चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपना लचीलापन साबित किया है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत और बेहतर तरीके से तैयार हुआ है। इस प्रक्रिया में भारत एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा जो मानव केंद्रित हो। हम न केवल वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं बल्कि निष्काम कर्म यानी सही कार्य को करने के सिद्धांत में भी हमारा विश्वास अटल है।

◆◆◆

टॉप गियर में रोड सेक्टर

वित्त वर्ष 2021 में जब दुनिया पर कोरोना की मार पड़ी थी, भारत में तब भी रोड कंस्ट्रक्शन जारी था। लॉकडाउन के बावजूद भारत ने 13,298 किलोमीटर हाइवे का निर्माण किया।

महाराष्ट्र में पिछले दिनों 75 किलोमीटर की सड़क 105 घंटे में बनाकर बने वर्ल्ड रेकॉर्ड ने सभी को चकित कर दिया। वैसे रोड सेक्टर के जानकारों के लिए यह कोई नहीं बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से यह सेक्टर, नित नए आयाम पर पहुंच रहा है। 100 किमी प्रति दिन की रफ्तार से सड़क बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि सरकार ने इस सेक्टर में फंडिंग बढ़ाकर 2022-23 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये की कर दी है। भारतमाला प्रॉजेक्ट, मुंबई–दिल्ली एक्सप्रेस वे, अमृतसर–जामनगर एक्सप्रेस वे और कई प्रॉजेक्ट्स एक साथ देश के सड़क मार्ग को बेहतर बनाने के लिए शुरू हैं। सड़क निर्माण के क्षेत्र में आंकड़े केवल एक नंबर भर ही हैं, हर दिन विस्तार की रफ्तार को देखते हुए हर लक्ष्य कुछ ही समय में बौने साबित होने लगते हैं।

भारत की रोड और हाइवे की विकास यात्रा ने काफी लंबा सफर तय किया है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भारत में 21,378 किलोमीटर नैशनल हाइवे थे और वर्तमान में यह 1.40 लाख किलोमीटर हो गया है। भारत के पास 63 लाख किलोमीटर का टोटल रोड नेटवर्क है, इसी के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन चुका है। टोटल रोड नेटवर्क में जहां नैशनल हाइवे 1,40,995 किलोमीटर है तो वहीं स्टेट हाइवे यानी राज्य हाइवे 1,71,039 किलोमीटर है। भारत के रोड नेटवर्क पर करीब 90 फीसदी पैसेंजर ट्रैफिक है तो वहीं 60 फीसदी माल ढुलाई का ट्रैफिक शामिल है। आजादी के 75 साल में भारत का रोड नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ा है और इसका दायरा और भी बढ़ाने के लिए तैयारियां पूरी हैं।

कोरोना काल में भी नहीं रुका काम

वित्त वर्ष 2021 में जब दुनिया पर कोरोना की मार पड़ी थी, भारत में तब भी रोड कंस्ट्रक्शन जारी था। लॉकडाउन के बावजूद भारत ने 13,298 किलोमीटर हाइवे का निर्माण किया। 2020-21 में हर दिन रेकॉर्ड 37 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने अब 60 किलोमीटर प्रति दिन सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2019-20 से 2023-24 के बीच नैशनल हाइवे का 60,000 किलोमीटर निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसमें फरवरी, 2022

तक 31,609 किलोमीटर बनकर तैयार है। महज 2020-21 के दौरान 553 नैशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। कुल 10,964 किलोमीटर की इन हाइवे पर 1.53 अरब रुपए का खर्च आ रहा है।

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश

भारत सरकार ने नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 111 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। ये राशि वित्त वर्ष 2019-2025 के लिए आवंटित की गई है। सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने 2025 तक 23 नैशनल हाइवे बनाने को मंजूरी दी है। कुल 34,800 किलोमीटर में बनने वाली इन हाइवे के निर्माण पर 5,35000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 2022 के अंत तक नैशनल हाइवे का 2 लाख किलोमीटर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार ने नैशनल गति शक्ति मास्टर प्लान भी जारी किया है। इसके जरिए सरकार मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट को विकसित करेगी। इसमें रेलवे, पोर्ट के अलावा सड़कें भी शामिल है।

2015 में सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया था। स्वदेश निर्मित इस तकनीक के जरिए 2018 तक 11 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर सड़क प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई हैं।

भारत माला प्रोजेक्ट

देश में सड़क और हाइव निर्माण के लिए भारत माला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 34,800 किलोमीटर नैशनल हाइवे तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पांच फ्लैगशिप हाइवे और 17 एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स

> **सरकार वैज्ञानिकों के साथ ऐसी सड़कें बनाने पर काम कर रही हैं, जो खुद को खुद ही रिपेयर कर लें। इसके लिए वैज्ञानिक डामर में स्टील फाइबर, आयरन ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स जैसे दूसरे मटीरियल डालते हैं।**

भी फेज वन के तहत निर्माण किए जा रहे हैं, इस पर सरकार 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत भी काम तेज हुआ है। जहां वित्त वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच सालाना 5900 किलोमीटर का काम नैशनल हाइवे पर हुआ था, वहीं वित्त वर्ष 2014-15 से सालाना 11,000 किलोमीटर तैयार हो रहा है। जल्द ही सरकार भारत माला फेज 2 शुरू करने वाली है।

रोड निर्माण में प्राइवेट प्लेयर

भारत में काफी लंबे समय तक रोड का निर्माण सरकारें ही करती थीं लेकिन अब सूरत बदल गई है। रोड कंस्ट्रक्शन में अब इघ् है यानी विदेशी कंपनियां भी निवेश कर सडक़ निर्माण भारत में कर सकती हैं। भारत में सड़क निर्माण अब PPP यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है। 201-20 में प्राइवेट सेक्टर ने 12,475 करोड़ रुपए का निवेश रोड कंस्ट्रक्शन में किया था। नवंबर, 2021 तक ये निवेश बढ़कर 15,164 करोड़ हो गया। इसके अलावा सरकार ने बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT-एन्युटी) और बिल्ड-ऑ परेट-ट्रांसफर (BOT-टोल) मोड के तहत 6722 किलोमीटर नैशनल हाइवे का निर्माण किया है। वित्त वर्ष 2021 तक 125 प्रोजेक्ट्स PPP मॉडल पर चल रहे थे। Fled होने से विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सड़क निर्माण में हिस्सा ले रही हैं।

इनोवेशन के साथ ग्रोथ

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय सड़क निर्माण को पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाला बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इसके लिए ही भारत में इलेक्ट्रिक हाइवे बनाने पर भी काम हो रहा है। सरकार 195 किलोमीटर लंबा ई-हाइवे जयपुर-दिल्ली ई-कॉरिडोर पर बनाएगी। यही प्लान 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए भी है। ई-हाइवे की खासियत ये है कि इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक ट्रक और बस ना सिर्फ प्रदूषण कम फैलाएंगे बल्कि खुद ही चार्ज भी हो जाएंगे। इस पर ट्रक और बसें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा सरकार का फोकस ग्रीन हाइवेज बनाने पर भी है। प्लास्टिक और रबड़ से बनाई जाने वाली ग्रीन हाइवेज ईंधन बचाने के साथ ही आपका वक्त भी बचाएगी। देश में 12,000 किलोमीटर ग्रीन हाइवेज बनाने का प्लान है। इसके जरिए देश के पर्यटन स्थलों और बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा।

नई टेक्नॉलजी पर भरोसा

सडक़ निर्माण में नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। नई तकनीकों से ना सिर्फ बेहतर सड़क निर्माण हो रहा है बल्कि इससे लागत में भी कमी आ रही है। 2015 में सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया था। स्वदेश निर्मित इस तकनीक के जरिए 2018 तक 11 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर सड़क प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई हैं। तकनीक के जरिए सडक़ों के रखरखाव पर आने वाले भारी-भरकम खर्च को कम करने की भी कोशिश हो रही है। सरकार वैज्ञानिकों के साथ ऐसी सड़कें बनाने पर काम कर रही हैं, जो खुद को खुद ही रिपेयर कर लें। इसके लिए वैज्ञानिक डामर में स्टील फाइबर, आयरन ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स जैसे दूसरे मटीरियल डालते हैं। सेल्फ-हीलिड रोड बारिश में भी ज्यादा बेहतर तरीके से टिकी रहती हैं।

रोड सेक्टर की चुनौतियां

देश में सड़क निर्माण तेजी से हो रहा है लेकिन इस सेक्टर के आगे भी कई चुनौतियां खड़ी हैं। नैशनल हाइवे नेटवर्क का करीब 55 फीसदी टू लेन है और सिर्फ करीब 24 फीसदी चार-लेन की। ऐसे में रोड का चौड़ीकरण करने की काफी ज्यादा डिमांड है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य भी रोड़ निर्माण को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सड़क निर्माण पर फोकस के बीच जो चिंता उबरकर आ रही है, वो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल। रोड़ कंस्ट्रक्शन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा मटीरियल की जरूरत होगी। वित्त वर्ष 2020 में कई राज्यों के पास मटीरियल

की कमी आई तो उन्होंने पास से सामान मंगवाया। मटीरियल की कमी से निर्माण की लागत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को प्लास्टिक वेस्ट समेत अन्य और आधुनिक मटीरियल को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए काम करना होगा ताकि लंबी अवधि में मटीरियल की कमी कोई दिक्कत ना बने। कंस्ट्रक्शन लाइन में कुशल श्रम की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। एक सर्वे के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर कुशल श्रमिकों की भारी कमी है। भारत में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए रिकगनाइज्ड प्रायर लर्निंग योजना शुरू की है। इस पर 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जिस तेजी से सडक़ निर्माण हो रहा है, उसी तेजी से ऑटो सेक्टर में भी डिमांड बढ़ रही है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग वाहन खरीद रहे हैं। इससे सडक़ निर्माण की गति और भी बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है।

75 साल का स्वर्णिम सफर

भारत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। इन 75 सालों में हर चीज की तरह रोड निर्माण भी बदला है। भारत में आदिकाल से ही सड़क निर्माण को काफी महत्व दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में सडक़ों की बजाय रोड नेटवर्क बनाने पर फोकस किया गया। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पहला गंभीर प्रयास 1943 में किया गया। इसे नागपुर प्लान नाम दिया गया। हालांकि ब्रिटिश हुकुमत और रियासतों के बीच बेहतर समन्वय ना होने की वजह से इस प्लान पर कोई एक्शन नहीं हो सका। भारत के आजाद होने के बाद पहली 5 वर्षीय योजना (1951-1956) सड़क निर्माण के लिए बनाई गई। इस योजना के तहत पहली बार देश में सड़कों को नैशनल हाइवे, राज्य हाइवे, जिला रोड और ग्रामीण सडक़ के तौर पर बांटा गया। अब सरकार ने सडक़ निर्माण पर काफी फोकस करना शुरू कर दिया था और इसी का नतीजा था –बॉम्बे प्लान। साल 1961 से 1981 के लिए एक 20 वर्षीय योजना बनाई गई। 20 साल के इस बॉम्बे प्लान के तहत ही देश में रोड नेटवर्क खासकर नैशनल और स्टेट हाइवे का विस्तार किया गया। ◆◆◆

> **"भारत में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए रिकगनाइज्ड प्रायर लर्निंग योजना शुरू की है। इस पर 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे।**

GHP GROUP
vision to reality

Empowering a child. Sharpening the mind.

Watch your child climb the ladder of success from the very first step he takes towards building a strong future for himself through the GHP Group. Dedicated to imparting education to every child, the group covers the entire journey of your child's education from nursery to graduation through its well established schools & colleges. Offering world class education, these institutions are well equipped to ensure your child's all round development.

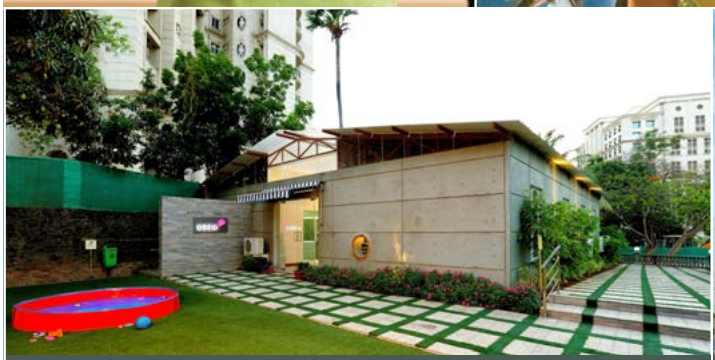

GSBB PRE-SCHOOL, POWAI

GOPAL SHARMA GROUP OF SCHOOLS

Call : 25700315 / 25700789 | E-mail : gsmspowai@gmail.com/ gsispowai@gmail.com | www.ghpeducations.com

GSMS
Gopal Sharma
Memorial School

PEHS
Powai English
High School

GSBB
Gopal Sharma
Blooming Buds Pre-School,
Hiranandani Complex

BVBS
Bal Vishwa Bharati School
& Junior College, Jaipur

CSC
Chandrabhan Sharma College
Arts, Science & Commerce

GSIS
Gopal Sharma
International School

Gopal Sharma Group of Schools, Powai Vihar, Powai, Mumbai – 400 076.

thoughtrains ghp-010112

मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य को लेकर चलना होगा

मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर, अपने दफ्तर की केबिन में कल्पवृक्ष की प्रतिकृति के आगे बेहद शांत चित्त होकर अपने काम में मशगूल दीपक नाइट्रेट के एमडी मौलिक मेहता केमिकल सेक्टर की अपार संभावनाओं के समीकरण बिठा रहे हैं। 2025 तक 300 बिलियन डॉलर की केमिकल इंडस्ट्री की उम्मीद के बीच केमिकल इंडस्ट्री में काम करने के कई चैलेंज भी हैं। आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के मौके पर हमने भारत की ग्रोथ जर्नी और केमिकल सेक्टर की संभावनाओं को लेकर प्यार और आदर की भावना के साथ काम करने वाले मौलिक मेहता से हमने विस्तृत बातचीत की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंशः-

मौलिक मेहता
सीईओ
दीपक नाइट्राइट लिमिटेड

भारत में ग्रोथ की संभावनाओं पर: चीन के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है, जहां घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों फ्रंट पर अपार संभावनाएं है। हमारा मीडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है, हर साल एक देश के बराबर। इस ग्रोथ के साथ ग्रो करना हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी है, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी।

कंपनी की ग्रोथ पर: दीपक फिनोलेक्स बनाना हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। हमने एक सोच पैदा की कि हमें आत्मनिर्भर भारत से आगे जाना होगा। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की सोच के साथ आगे बढ. ना होगा।

हमेशा प्रोग्रेस केवल नंबर में नहीं आंकी जा सकती, आंकड़े तो बायप्रॉडक्ट्स होते हैं। दीपक में हम परिवार की तरह काम करते हैं। 3,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जबर्दस्त संभावनाएं हैं। हम उसे एक-दूसरे का हाथ पकडकर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा उद्यमी हैं, पिछले 10 साल में इस क्षेत्र में चमत्कार हुआ। टेक्नॉलजी, कैपेक्स, सरकार की मदद से 2030 तक का समय भारत का होगा।

अपनी शुरुआत पर : मैंने फैक्ट्री असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, मैंने तीनों शिफ्ट में काम किया है। ग्रोथ करना है तो आपको सभी के साथ लगकर काम करना होगा। When you are with people, people are with you. आज हम आपस में हर विषय पर चर्चा करते हैं, रास्ता निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं।

प्रॉडक्शन में कहां चुनौती में अवसर निकला ?

केमिकल इंडस्ट्री में सप्लाई चेन की समस्या काफी है। हमने फिनॉल प्लांट लगाया तो 2 लाख टन का था, आज यह उससे काफी बड़ा हो गया है। विश्व भर में हर फिनॉल प्लांट की सामग्री पाइप लाइन से है। हमारे दाहेज के प्लांट में 1,000 किमी की दूरी तय करके रॉ मटिरियल आता है। यह हमारी दिक्कत थी, हमने इसे मौके के रूप में देखा।

चूंकि हर प्लांट को मैनटेंनेस के लिए कुछ समय बंद रहना पड़ता है लेकिन हम कई जगहों से मटिरियल लेते हैं, इसलिए हमारा प्लांट कभी बंद नहीं होता। इस तरह से हमने चुनौती में अवसर निकाला। हालांकि,हम इसकी व्यवस्था में काफी खर्च करते हैं, सुरक्षा के लिए हमने काफी कड़ी व्यवस्था की है। सारे टैंकर में जीपीएस लगे हैं, हर 100 किमी पर हमारा व्यक्ति है, जो कि आवश्यक सामग्री के साथ उपलब्ध होता है। ताकि जरूरत के समय वह टैंकर तक पहुंच सके।

केमिकल इंडस्ट्री पर: केमिकल इंडस्ट्री में एक खास बात यह है कि जब कोई नई कंपनी आती है तो हम उसे मौके के तौर पर देखते हैं। उनका प्रॉडक्ट मेरा रॉ मटिरियल हो सकता है, मैं उसे कुछ सप्लाई कर सकता हूं। स्पर्धा एक चीज है, लेकिन यह हमारे लिए मौका होता है। हमें भविष्य की डिमांड को ध्यान में रखकर प्लांट लगाने होंगे।

सीएसआर गतिविधि: हम सालों से समाज के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। हमने सीएसआर तबसे शुरू कर दिया था, जब इसे लेकर कोई नियम भी नहीं था। हमारा मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाकर ही समाज की प्रगति हो सकती है। इसीलिए हम मां की गर्भावस्था से लेकर बच्चे के स्कूल, स्किल ट्रेनिंग तक सपोर्ट करते हैं। हम नशा मुक्ति के लिए भी काम करते हैं, ताकि घर में खुशहाली और संपन्नता बनी रहे।

मुंबई से दूरी पर: मुंबई से दूरी तभी महसूस होती है, तब हमें इंटरनैशनल ट्रैवल करना होता है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने में ही यहां से 2-3 घंटे लग जाते हैं। बाकी हमारी जरूरत कम हैं, हम अपने लोगों के साथ काम पर फोकस करते हैं। बॉलिवुड और लाइफस्टाइल का कोई खास आकर्षण नहीं है।

देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर: हमें इन्फ्रास्ट्रकचर पर बड़े पैमाने में खर्च करना होगा, वैसे सरकार ऐसा कर भी रही है। आज देश मंक सामान भेजने से ज्यादा आसान विदेश में सामान भेजना है। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से सभी सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमारी ग्रोथ रॉकेट की तरह हो सकती है।

व्यक्तिगत जिंदगी पर: मुझे किताब पढ़ने का शौक है। अब तक एक हजार से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूं। परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। स्विमिंग, जिम भी करता हूं। वैसे, जब आप अपने काम को एन्जॉय करते हैं तो उसमें अपने आप ही एनर्जी आ जाती है। ◆◆◆

बुलेट स्पीड में दौड़ता रेलवे का ग्रोथ इंजन

दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेल की उपलब्धियों की एक झलक मात्र है। देश के सबसे बड़े एम्पलॉयर इंडियन रेलवे अपने समृद्ध इतिहास और दूरगामी विजन की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को बुलेट स्पीड से दौड़ाने के लिए प्रमुख इंजन साबित हो रहा है। नैशनल रेलवे प्लान के अनुसार, अगले कुछ सालों में रेलवे ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करेगा। आजादी के 75 सालों में रेलवे देश की प्रगति में एक अहम हिस्सेदार बनकर सामने आया है।

“ शहरों के बीच की दूरी कम करने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की संकल्पना पर काम किया जा रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए काम फुल स्पीड में चल रहा है।

बढ़ेगा फ्रेट का हिस्सा

फ्रेट यानी माल ढुलाई का हिस्सा बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर रेलवे आगे बढ़ रही है। इसे हासिल करने के लिए दो तरीकों से काम किया जाएगा, 1. माल गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाएगी और 2. चुनिंदा कमोडिटी की ढुलाई की दरें घटाई जाएंगी।

भारतीय रेल ने 2051 तक ढुलाई 15,500 मैट्रिक टन ढुलाई का लक्ष्य रखा है। 2009 से 2018 के बीच ढुलाई 3.74 प्रतिशत सीएजीआर (कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट) से आगे बढ़ा है। ऐसे में, रेलवे द्वारा तय किया गया आगामी लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है लेकिन तय रोड मैप के लिहाज से तय करने में असंभव नहीं है।

देश में रेलवे द्वारा माल ढुलाई का हिस्सा 26 प्रतिशत है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के 65 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। रेलवे का लक्ष्य इसी को बढ़ाकर 45 प्रतिशत ले जाने का है।

रेलवे अपने माल गाड़ियों की स्पीड चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। जिसके द्वारा 2026 तक 30 किमी प्रति घंटा, 2031 तक 35 किमी प्रति घंटा, 2041 तक 40 किमी प्रति घंटा और 2051 तक 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

पिछले कुछ समय से रेलवे ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी का बेहतरीन माध्यम बनकर सामने आया है। हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष में रेलवे को इस मद से 300 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है जो कि उससे पहले के साल से दोगुना से भी ज्यादा है। इसमें सबसे अहम हिस्सा किसान रेल का रहा, जिसकी सहायता से रेलवे ने किसानों के उत्पाद को गंतव्य तक पहुंचाया। कम समय में सुरक्षित तरीके से उत्पाद खेत से ग्राहक के हाथ तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद हुई है।

डीएफसी की अहम भूमिका

फ्रेट आवाजाही का जाल बिछाने में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) बहुत अहम हिस्सा निभाएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी पर काम तीव्र गति से शुरू है। जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, ईस्ट-वेस्ट डीएफसी जो कि पालघर से दानकुनी तक 2328 किमी का, नॉर्थ-साउथ डीएफसी जो कि पलवल के पास से शुरू होगा और चेन्नै के पास अरक्कोनल तक जाएगा, इसकी लंबाई 2327 किमी होगी। तीसरी लाइन होगी, ईस्ट कोस्ट डीएफसी। यह खडग़पुर के पास हिजली से शुरू होकर विजयवाड़ा तक जाएगी, जो कि 1114 किमी की दूरी है।

ईस्टर्न डीएफसी जो कि लुधियाना से लेकर यूपी होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक जाने वाली इस लाइन के लिए 99 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। 50 प्रतिशत से अधिक तैयार हो चुका यह प्रॉजेक्ट मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वेस्टर्न डीएफसी जो कि मुंबई के पास जेएनपीटी से शुरू होकर दादरी, उत्तर प्रदेश तक जाने वाला है, को भी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद, जेएनपीटी से निकलकर एनसीआर तक जिस ट्रेन को पहुंचने में 2-3 दिनों का समय लगता है, वो 24 घंटे के अंदर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाने के बाद देश के विभिन्न कोने में माल पहुंचाना आसान होगा। इसका एक दूसरा फायदा पैसेंजर ट्रेनों को भी मिलेगा, क्योंकि फ्रेट ट्रेनों के उन पटरियों से हटने के बाद यह भी अपनी रफ्तार से चल सकेंगी। एक समय, रेलवे देश के ट्रांसपोर्ट का 80 प्रतिशत हिस्सा ले जाया करता था लेकिन समय के साथ यह हिस्सेदारी केवल 25 प्रतिशत पर आ गई।

प्लेन की स्पीड में ट्रेन

शहरों के बीच की दूरी कम करने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की संकल्पना पर काम किया जा रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए काम फुल स्पीड में चल रहा है। इसके तैयार हो जाने के बाद 508 किमी की यह दूरी महज 2 घंटों में पूरी की जा सकेगी। यानी, जिस स्पीड से लोग प्लेन में सफर करते हैं, उसी स्पीड से रेल यात्रा हो सकेगी। यह आजादी के 75 सालों में देश के प्रगति पथ पर अग्रसर होने का पर्याप्त संकेत दे रहा है। हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रॉजेक्ट के लिए कई अड़चनों को दूर कर दिया है। इसकी

खासियत यह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बिजनेस सेंटर बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स (बीकेसी) से यह शुरू होगी।

इसके अलावा, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर जो कि 300 से 700 किमी की दूरी पर हैं, को अन्य विभिन्न पैरामीटर के आधार पर हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत, दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-जालंधर-अमृतसर; दिल्ली-आगरा-कानपुर-लखनऊ-वाराणसी जैसे रूट प्रमुख हैं।

स्वर्णिम इतिहास

रेलवे का इतिहास बड़ा समृद्ध है। ब्रिटिश राज से आधुनिक भारत तक की यात्रा यह अपने में संजोए हुए है। 16 अप्रैल, 1853 को बोरिबंदर (मुंबई) से ठाणे के बीच 400 यात्रियों को लेकर पहली पैसेंजर ट्रेन चली। 1980 आते-आते स्टीम

इंजन पूरी तरह से खत्म हो गए और दौर आ गया इलेक्ट्रिक इंजनों का। 2002 भी रेलवे के इतिहास में यादगार वर्ष रहा, जब टिकटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज हो गए और विंडो पर टिकट के लिए लंबी कतार का विकल्प मिल गया। 169 सालों से रेलवे न केवल आवाजाही का माध्यम मात्र है बल्कि अलग-अलग रूपों में अर्थव्यवस्था की धुरी को भी सपोर्ट कर रही है।

वर्ल्ड क्लास स्टेशन

अगले कुछ सालों में देश के प्रमुख स्टेशनों का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नए स्टेशन परिसर एयरपोर्ट की तरह चमकेंगे। देश के 400 से ज्यादा स्टेशनों को चरण बद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसमें सीएसटी, भोपाल, सूरत, आनंद विहार, गांधी नगर भी शामिल हैं। इस प्रॉजेक्ट में करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। इनके बन जाने के

169 सालों से रेलवे न केवल आवाजाही का माध्यम मात्र है बल्कि अलग-अलग रूपों में अर्थव्यवस्था की धुरी को भी सपोर्ट कर रही है।

बाद स्टेशनों पर फूड हब, छोटे रिटेल स्टोर, सैलून समेत अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

ग्रीन रेल

रेलवे पिछले कुछ सालों से पर्यावरण अनुकूल कदम तेजी से उठा रही है। इसी दिशा में वह पूरे रूट का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन करने के काम में मिशन मोड से आगे बढ़ रही है। हाल ही में कोंकण रेलवे ने अपने पूरे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। रेलवे के 64,689 किलोमीटर के रूट में से 52,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, सभी ट्रेनों में बायो-टॉइलेट लगाए जा चुके हैं। स्टेशन परिसर में सोलर पैनल का भी बड़े पैमाने में उपयोग किया जा रहा है।

फंडिंग पर फोकस

केंद्र सरकार ने 1.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन 2022-23 के लिए रेलवे को किया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। रेलवे को इस साल पैसेंजर रेवेन्यू 58,500 करोड़ रुपये और गुड्स रेवेन्यू 1,65000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। जाहिर बात है, कैपिटल एक्सपेंडेचर को बढ़ाकर रेलवे अपना मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में ग्रोथ की पटरी पर दौड़ने वाली रेल का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन बनेगा।

देश के 400 से ज्यादा स्टेशनों को चरण बद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसमें सीएसटी, भोपाल, सूरत, आनंद विहार, गांधी नगर भी शामिल हैं।

भी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद, जेएनपीटी से निकलकर एनसीआर तक जिस ट्रेन को पहुंचने में 2-3 दिनों का समय लगता है, वो 24 घंटे के अंदर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाने के बाद देश के विभिन्न कोने में माल पहुंचाना आसान होगा। इसका एक दूसरा फायदा पैसेंजर ट्रेनों को भी मिलेगा, क्योंकि फ्रेट ट्रेनों के उन पटरियों से हटने के बाद यह भी अपनी रफ्तार से चल सकेंगी। एक समय, रेलवे देश के ट्रांसपोर्ट का 80 प्रतिशत हिस्सा ले जाया करता था लेकिन समय के साथ यह हिस्सेदारी केवल 25 प्रतिशत पर आ गई।

प्लेन की स्पीड में ट्रेन

शहरों के बीच की दूरी कम करने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की संकल्पना पर काम किया जा रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए काम फुल स्पीड में चल रहा है। इसके तैयार हो जाने के बाद 508 किमी की यह दूरी महज 2 घंटों में पूरी की जा सकेगी। यानी, जिस स्पीड से लोग प्लेन में सफर करते हैं, उसी स्पीड से रेल यात्रा हो सकेगी। यह आजादी के 75 सालों में देश के प्रगति पथ पर अग्रसर होने का पर्याप्त संकेत दे रहा है। हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रॉजेक्ट के लिए कई अडचनों को दूर कर दिया है। इसकी खासियत यह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बिजनेस सेंटर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से यह शुरू होगी।

इसके अलावा, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर जो कि 300 से 700 किमी की दूरी पर हैं, को अन्य विभिन्न पैरामीटर के आधार पर हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत, दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-जालंधर-अमृतसर; दिल्ली-आगरा-कानपुर-लखनऊ-वाराणसी जैसे रूट प्रमुख हैं।

स्वर्णिम इतिहास

रेलवे का इतिहास बड़ा समृद्ध है। ब्रिटिश राज से आधुनिक भारत तक की यात्रा यह अपने में संजोए हुए है। 16 अप्रैल, 1853 को बोरिबंदर (मुंबई) से ठाणे के बीच 400 यात्रियों को लेकर पहली पैसेंजर ट्रेन चली। 1980 आते-आते स्टीम ईंजन पूरी तरह से खत्म हो गए और दौर आ गया इलेक्ट्रिक इंजनों का। 2002 भी रेलवे के इतिहास में यादगार वर्ष रहा, जब टिकटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज हो गए और विंडो पर टिकट के लिए लंबी कतार का विकल्प मिल गया। 169 सालों से रेलवे न केवल आवाजाही का माध्यम मात्र है बल्कि अलग-अलग रूपों में अर्थव्यवस्था की धुरी को भी सपोर्ट कर रही है।

वर्ल्ड क्लास स्टेशन

अगले कुछ सालों में देश के प्रमुख स्टेशनों का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नए स्टेशन परिसर एयरपोर्ट की तरह चमकेंगे। देश के 400 से ज्यादा स्टेशनों को चरण बद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसमें सीएसटी, भोपाल, सूरत, आनंद विहार, गांधी नगर भी शामिल हैं। इस प्रॉजेक्ट में करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। इनके बन जाने के बाद स्टेशनों पर फूड हब, छोटे रिटेल स्टोर, सैलून समेत अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

ग्रीन रेल

रेलवे पिछले कुछ सालों से पर्यावरण अनुकूल कदम तेजी से उठा रही है। इसी दिशा में वह पूरे रूट का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन करने के काम में मिशन मोड से आगे बढ़ रही है। हाल ही में कोकण रेलवे ने अपने पूरे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। रेलवे के 64,689 किलोमीटर के रूट में से 52,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, सभी ट्रेनों में बायो-टॉइलेट लगाए जा चुके हैं। स्टेशन परिसर में सोलर पैनल का भी बड़े पैमाने में उपयोग किया जा रहा है।

फंडिंग पर फोकस

केंद्र सरकार ने 1.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन 2022-23 के लिए रेलवे को किया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। रेलवे को इस साल पैसेंजर रेवेन्यू 58,500 करोड़ रुपये और गुड्स रेवेन्यू 1,65,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। जाहिर बात है, कैपिटल एक्सपेंडेचर को बढ़ाकर रेलवे अपना मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में ग्रोथ की पटरी पर दौड़ने वाली रेल का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन बनेगा। ◆◆◆

UPTO 70% OFF EVERYDAY
FLF FUTURE LIFESTYLE FASHIONS
*Terms & Conditions Apply.
200 BEST BRANDS | 20%-70% OFF | SALE 365 DAYS
KARMA
BF BRAND FACTORY
BEST BRANDS ▸ SMART PRICES
SKECHERS
Levi's
Lee Cooper
BUFFALO
W
VAN HEUSEN
UNITED COLORS OF BENETTON.
U.S. POLO ASSN.
GINI & JONY
PETER ENGLAND
23 CITIES. 55 STORES
www.brandfactoryonline.com | brand factory | CUSTOMER CARE NO.: 18002101888

रामदेव अग्रवाल
चेयरमैन, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप

जितना 75 सालों में किया उससे ज्यादा अगले 10 सालों में करेंगे

“ हमने शून्य से शुरुआत की थी, जुनून के साथ काम करते हैं। इतना भरोसा है कि पिछले १० साल में जो हुआ, उससे ज्यादा अच्छा अगले १० सालों में होगा। किसी भी उद्यमी को यह नहीं पता होता है कि आगे भविष्य कैसा होगा लेकिन उसके फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए। हमारे पास आत्मविश्वास है, टैलेंट है, टेक्नॉलजी है, हम इसी के बूते आगे बढ़ेंगे।

चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने मुंबई आए रामदेव अग्रवाल आज मार्केट किंग बन चुके हैं। 1987 में अपने मित्र मोतीलाल ओसवाल के साथ मिलकर कंपनी बनाने वाले रामदेव वॉरेन बफेट से प्रेरित हैं।

भारत की जनसंख्या को ही ग्रोथ का ईंधन मानने वाले अग्रवाल देश का निकट भविष्य काफी सुनहरा देखते हैं। उनका मानना है कि एक गरीब आदमी जब उठता है जो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार उठ जाता है तो पूरा कर्व ही बदल जाता है। इसके बाद वह रॉकेट की रफ्तार से उड़ता है। हमने भारत की ग्रोथ यात्रा, शेयर बाजार, युवाओं के लिए नए अवसर समेत अन्य विभिन्न मुद्दों पर बात की मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

मार्केट में बढ़ रहे भरोसे पर?

भारत की ट्रेडिंग हिस्ट्री काफी पुरानी है। इंडिया टॉप 3-4 ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मे आता है। लेकिन लोगों की सीमित आय और अन्य कारणों से यहां भागीदारी काफी कम थी। लेकिन अब रैपिड चेंज हो रहा है, बाजार बहुत ब्रॉड हो रहा है। सेबी के चलते मार्केट बहुत सेफ हो गया है। टेक्नॉलजी, इंटरनेट, टेलिकॉम ने ईज ऑफ इंटरिंग को बहुत आसान कर दिया है। हर महीने 25 से 30 लाख लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 3-4 सालों में 200 मिलियन लोग आ जाएंगे। देश के लिए यह भीड़ ही असेट है, यह बहुत पावरफुल है। अब लोगों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पता चल रहा है कि महंगाई को पीछे करना है तो मार्केट में आना होगा।

मार्केट का प्रगति में कितना योगदान है?

आर्थिक विकास की रीढ़ मार्केट ही है। आज जोमैटो जैसी कंपनियां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दी हैं, उन्हें मार्केट ने सपोर्ट किया। मार्केट आपको खाद देता है। आज सब कुछ

आपस में जुड़ा हुआ है, लोगों को लोकल और ग्लोबल कैपिटल एक साथ मिल रहे हैं। अच्छा काम करोगे, तो पूरी दुनिया पैसे लगाएगी। हमने भी इसी तरह से प्रगति की। आज हम 200-300 करोड़ रुपये डिविडेंट बांट रहे हैं। इसी मार्केट के भरोसे हमने पिछले 20 सालों में बहुत ग्रोथ की है, अमेरिका भी इस तरह से बढ़ा था।

मार्केट में आने वालों के लिए क्या मंत्र देंगे ?

हमने इन्वेस्टिगेट किया, स्पेक्युलेशन नहीं। जल्दबाजी न करें, सट्टा न करें, लीवरेज न करें। बहुत जल्दी पैसा नहीं बनता। धैर्य रखिए, कंपाउंडिंग की पावर पर भरोसा रखिए। इक्विटी आखिरी में पैसा देता है, लेकिन जब देता है तो बहुत देता है। अगर जीतना है तो आखिरी लाइन तक पहुंचो, शांति रखो।

विदेशों निवेशकों की चाल पर ?

अनिश्चितता ही बाजार का सबसे अनोखा पहलू है। एफआईआई ने काफी पैसे निकाले हैं। वो आएंगे, लेकिन कब यह कहना मुश्किल है। भारत का बाजार काफी मजबूत है।

भारत के अब तक के सफर पर ?

देखिए, 1947 से 82-83 तक का सफर तो मैं केवल किस्सों में पढ़ता हूं। लेकिन इसके बाद से तो खुद महसूस कर रहा हूं। पहले ट्रेन और फ्लाइट में सफर करना कितना मुश्किल था, अफोर्डेबल ही नहीं था। लोगों के पास सेविंग नहीं थी। हम विदेश से भी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। उदारीकरण के बाद से चीजें बदलना शुरू हुई, हम विश्व के करीब आए। एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, इससे काफी पैसे आए, आगे इसकी रफ्तार और बढ़ेगी और पैसे आएंगे। अगले 20 सालों में 10 से 15 ट्रिलियन हम इससे कमा सकते हैं।

मोतीलाल ओसवाल कंपनी की ग्रोथ पर ?

हमने शून्य से शुरुआत की थी, जुनून के साथ काम करते हैं। इतना भरोसा है कि पिछले 10 साल में जो हुआ, उससे ज्यादा अच्छा अगले 10 सालों में होगा। किसी भी उद्यमी को यह नहीं पता होता है कि आगे भविष्य कैसा होगा लेकिन उसके फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए। हमारे पास आत्मविश्वास है, टैलेंट है, टेक्नॉलजी है, हम इसी के बूते आगे बढ़ेंगे। फाइनैंशल मार्केट में आगे 10 गुना संभावना बढ़ेगी।

भारत की आगे की जर्नी कैसी दिख रही है ?

हर व्यक्ति, हर कंपनी और हर देश का एक समय आता है। अमेरिका अभी 32 से 35 ट्रिलियन

डॉलर पर है, हम 3 पर हैं। एक बहुत लंबा सफर है लेकिन यह बहुत रोचक रहेगा। जब तलवार रफ्तार में चलेगी तो कौन रोक पाएगा ? हाथी जब दौड़ता है तो उसकी बात ही अलग होती है। हम मजबूत लीडरशिप, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिफॉर्म्स के बूते आगे बढ़ रहे हैं। यह जरूरी है कि आप बाजार को डिस्टर्ब न करें, इंटरप्रेन्योर को डिस्टर्ब न करें क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एसेट यही तो हैं। यदि आपको आर्थिक प्रगति करनी है तो व्यापार और व्यापारी को सपोर्ट करें और हम ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए, पिछले 20 सालों में सन फार्मा, इनफोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी और न जाने कितनी मजबूत कंपनियां खड़ी हुई। आगे तो और मौके हैं। हमने 75 सालों में जितनी ग्रोथ की, उतनी या उससे भी ज्यादा हम अगले 10 सालों में करेंगे।

युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ?

यदि आपको नौकरी करनी है तो मेरे पास कोई अडवाइज नहीं है। यदि आपको बिजनेस करना है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जुनून होना चाहिए। पूरे विश्व में इसी तरह होता है। आप बायोग्राफी पढ़िए, टेस्ला 18 घंटे कोडिंग करता था। बस, आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। देश का भविष्य बहुत ब्राइट है, आपको रिस्क लेना होगा, संभावनाएं अब ग्लोबल हो चुकी हैं। जुनून, मजबूत वैल्यू सिस्टम और अच्छी रिलेशनशिप के बूते आप कुछ भी कर सकते हैं। 25 साल का लक्ष्य 15 साल में हासिल कर सकते हैं।

◆◆◆

BRAND FACTORY
BEST BRANDS ▸ SMART PRICES

SKECHERS | Levi's | Lee Cooper | BUFFALO | W | VAN HEUSEN | UNITED COLORS OF BENETTON. | U.S. POLO ASSN. | GINI & JONY | PETER ENGLAND

23 CITIES. 55 STORES
www.brandfactoryonline.com | brand factory | CUSTOMER CARE NO.: 18002101888

भारत बनेगा विश्व लीडर

वीरेन्द्र म्हैस्कर
सीएमडी
आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपर्स लिमिटेड

इंटरव्यू

हा

इवे निर्माण को केवल इंजिनियरिंग की बजाय पर्यावरण और लोगों से इमोशनल बॉन्डिंग का जरिया मानने वाले विरेंद्र म्हैस्कर ने पिछले दो दशक में कई कीर्तिमान रचे हैं। विरेंद्र ने सिविल डिप्लोमा कर पिता के साथ 1990 में काम करना शुरू कर दिया लेकिन संभावनाओं के दरवाजे तो 1995 में खुले। रोड सेक्टर में प्राइवेट प्लेटर की एंट्री खुलते ही भविष्य में ग्रोथ के हाइवे उन्हें नजर आने लगे। उदारीकरण के बाद भारत की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए म्हैस्कर को गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ने की राह दिखने लगी। पहले से ही टोल कलेक्शन के दौरान जनता द्वारा खराब रास्तों की लगातार शिकायतों के अनुभव ने उनके मन में इस क्षेत्र में क्वॉलिटी कंस्ट्रक्शन की जरूरत का बड़ा स्वरूप सामने ला दिया। 1995 में देश के पहले बिल्ट- ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) आधारित ठाणे-भिवंडी बायपास का काम मिला। रोड सेक्टर के फर्राटेदार मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए महज 27 साल की उम्र में विजन और मिशन के साथ विरेंद्र म्हैस्कर ने 1998 में आईआरबी की स्थापना कर दी। फिर अगले कुछ सालों में ही कंपनी देश में बीओटी का काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फाइनैंशल डिसिप्लिन, शांत चित्त से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने वाले विरेंद्र के सामने शुरुआत में कई चुनौतियां आई। सरकार की ओर से काम तो मिल रहा था लेकिन दिक्कत थी फंडिंग की। टोल कलेक्शन के आधार पर फंडिंग मिलना आसान नहीं थी। विरेंद्र ने इक्विटी और कॉर्पोरेट सिक्युरिटी के दम पर फंडिंग हासिल की। समय से पहले कई प्रॉजेक्ट पूरे किए और फिर क्या था, आगे की राह आसान होती चली गई। 6,300 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक के साथ अगले कुछ सालों में गतिविधियां और अधिक तेज होने वाली हैं। फिलहाल, कंपनी गंगा एक्सप्रेस-वे के दिल्ली की ओर के फेज १ में मेरठ से बदांयू के प्रॉजेक्ट में जुटी हुई है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव काल में प्रधानमंत्री के गति शक्ति अभियान के तहत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिल रहे पुश से भी भविष्य में इसकी संभावना और बेहतर ही नजर आ रही है। रोड सेक्टर की रफ्तार, भारत में भविष्य की ग्रोथ, भविष्य के लक्ष्य समेत अन्य विभिन्न मुद्दों पर **अभ्युदय वात्सल्यम् के एडिटर इन चीफ आलोक रंजन तिवारी** ने बात की **आईआरबी के सीएमडी वीरेन्द्र दत्तात्रेय म्हैसकर** से। पेश हैं प्रमुख अंश:

भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बड़ा योगदान होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस क्षेत्र के कितने योगदान की परिकल्पना आप करते हैं?

हां, भारत को ५ ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सड़क के बुनियादी ढांचे का बड़ा योगदान होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार वित्त वर्ष 2025 तक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 111 लाख करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सेक्टर को 19% (यानी FY 2025 तक केपेक्स का 20 लाख करोड़ रुपये) के आवंटन का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है।

जहां तक आईआरबी समूह के योगदान का संबंध है, इसकी सराहना करने की आवश्यकता है कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास क्षेत्र में भारत की पहली बहुराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी आज 22 राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से 12,000 से अधिक लेन किलोमीटर का और 600 अरब उद्यमी मूल्य की परिसंपत्ति का प्रबंधन कर रही है। एक समृद्ध डोमेन विशेषज्ञता और दो दशकों से अधिक अनुभव के साथ और अपनी सर्वोच्च रणनीतिक प्राथमिकता, यानी **द नेशन फर्स्ट** के अनुरूप, कंपनी राष्ट्रीय विकास एजेंडे में योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

भारतीय 30 किलोमीटर सड़क बनाने की दैनिक उपलब्धि देख रहे हैं और 2024 तक निर्धारित लक्ष्य 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का है। किस तरह से विस्तार आप देख रहे हैं?

भारत में सड़क विकास में मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड विस्तार शामिल है, यानी मौजूदा सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 4 से 6 लेन आदि तक चौड़ा करना। मौजूदा सड़क, बिटुमिनस सड़क है, इसलिए सड़क का चौड़ीकरण भी बिटुमिनस सड़क के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, स्टील की आवश्यकता सड़क की संरचना पर निर्भर करती है।

भारत में हाई स्पीड एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं; हालांकि, अन्य सड़कों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए, कौन-सी विश्व स्तरीय और उन्नत तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए?

वर्तमान में हम राजमार्गों के निर्माण के लिए विश्व की सर्वोत्तम मशीनरी और सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा बनाए गए राजमार्गों की गुणवत्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजमार्गों के बराबर है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने आईआरबी द्वारा प्रबंधित/विकसित की गई 9 परियोजनाओं (उनके द्वारा मूल्यांकन की गई हमारी 10 परियोजनाओं में से) के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग और मूल्यांकन पद्धति के अनुसार एक परियोजना के लिए बहुत अच्छी रेटिंग प्रदान की है। क्षमता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण में सुधार के उद्देश्य से राजमार्गों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया गया।

लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र एक साथ सकल घरेलू उत्पाद का 15% योगदान देता है। सड़क क्षेत्र, लॉजिस्टिक और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण घटक है। आप इन क्षेत्रों के समग्र विकास का विश्लेषण कैसे करते हैं?

सकल घरेलू उत्पाद और यातायात वृद्धि के बीच लगभग 90 से 100% को-रिलेशन है। हम अपनी 20 से अधिक रोड कन्सेशन पर हर दिन लगभग 10 लाख उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा दे रहे हैं। राष्ट्र के विकास में अंतिम माइल कनेक्टिविटी होने के कारण सड़क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय सुधारों को लागू करने के लिए नियामक सुधारों में आप क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं?

सरकार ने भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के मामले में भूमि मालिकों के लिए पर्याप्त मुआवजा (जो मुआवजे के रूप में सर्कल रेट के 3 से 10 गुना तक है) जैसे कई सुधार किए हैं। इसके अलावा, कोविड महामारी के दौरान, सरकार ने रियायत अवधि को न्यूनतम 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करके राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया है। भारत तेजी से विकास पथ पर है, इसमें न केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता होगी बल्कि निजी क्षेत्र से भी पूंजी योगदान की आवश्यकता होगी। निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, सरकार को सड़क क्षेत्र में BOT और TOT के आधार पर और अधिक परियोजनाओं के साथ आना होगा।

◆◆◆

DESAI HARMONY

WADALA (W)

MAHA RERA NO.P51900009455

Follow Us On

Swimming Pool

Ample Car Parking

Podium Garden

Health & Fitness Center

Luxurious 2, 3 & 4 BHK Apartments

Centrally located in the heart of the city (Wadala, West), Desai Harmony makes your life convenient as the best of the metropolis surrounds you. It's a two minutes drive from all the major infrastructure facilities and the most happening destinations of Mumbai. **Stay closer to life.**

Call :+91 9209206206 / +91 75061 18929 / +91 98198 51644

E : sales@sparkdevelopers.in | sms Spark Wadala to 56677

Our Projects At : Worli | Andheri | Ghatkopar | Vile-Parle

Site Address : Desai Harmony, G.D Ambekar Marg, Opp. Hanuman Industrial Estate, Near Dadar Workshop, Wadala, Mumbai - 400 031

Corp. Office : 102, Saroj Apartment, 1st Floor, N.P. Marg, Opp. Matunga Gujarati Club, King's Circle, Matunga, Mumbai – 400 019

SPARK DEVELOPERS
creating world for you

www.sparkdevelopers.in

Disclaimer: This advertisement is merely conceptual and is not a legal document. It cannot be treated as a part of final purchase agreement. All dimensions are approximate and subject to construction variances. The developer reserves sole rights to amend architectural specifications during development stages.

Invesco Mutual Fund

Market twists, turns, ups, downs.

Meet them all with a smile.

Invesco India Flexi Cap Fund

(An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks)

Invest in a flexible fund that responds to opportunities across market caps.

On the journey of life, the ability to adapt is key to surviving challenging situations. In financial markets too, where unpredictability is the norm, being flexible can help you move in the direction of opportunity. Pick a scheme with the flexibility to invest across large, mid and small caps so that no matter how the market twists and turns, you can keep moving towards your goals.

To invest, speak to your Mutual Fund Distributor or visit **invescomutualfund.com**

Call 1800 209 0007
SMS 'Invest to 56677

Follow us on

Suitable for investors who are seeking*

- capital appreciation over long term
- investments in a dynamic mix of equity and equity related instruments across largecap, midcap and small cap stocks

***Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.**

RISKOMETER

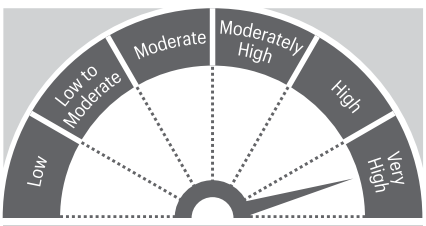

Investors understand that their principal will be at Very High Risk

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

TITELNO. MAHHINO7214/13/A2009-TC ■ REGISTRATION NO : MAHHIN/2009/30744
BY OFFICE THE REGISTRAR OF NEWS PAPERS FOR INDIA,
MINISTRY OF INFORMATION & BRODCASTING, GOVT.OF INDIA

हम सब की है यही पुकार । हरा-भरा हो यह संसार ।।

जनहित में प्रकाशित